

घाटती घाटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 204 - मंगलवार 26 - मई 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.-CHHHN/2004/15050, डाक पंजीकरण क्र. 13/Surguja JKP 2026-2028

नीट पेपर लीक पर भड़का सुप्रीम कोर्ट कहा...पुरानी गलतियों से सबक क्यों नहीं लिया, एनटीए से मांगा सीधा जवाब...

नई दिल्ली, 25 मई 2026। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि पुराने मामलों से कोई सबक नहीं सीखा गया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अफसरों के हथ-पांव फूल गए हैं। दिल्ली की इस हलचल का सीधा असर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में दिख रहा है, जहाँ हजारों छात्र दोबारा परीक्षा होने की उम्मीद में बैठे हैं।

केन्द्र सरकार को नोटिस, एनटीए से सीधे सवाल...

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यू.एनटीए परीक्षा में हुई धांधली को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस थमा दिया है। कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ, जिसे पुराने आदेशों के बाद बनाया जाना था? अदालत ने इस मामले में चल रही छिल्लाई पर गहरी नज़र जताई है। रायपुर के स्थानीय कॉन्ग्रेस सेंटर्स में सुबह से ही छात्र और उनके माता-पिता टीवी स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए बैठे हैं।

डॉक्टरों के संगठन ने खतरनाक अदालत का दरवाजा

यह पूरी सुनवाई फेब्रुअरी में ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर एक याचिका पर हो रही है। वकील तन्वी दुबे के जरिए कोर्ट पहुंची इस याचिका में एनटीए के काम करने के तरीके को बड़ी नाकामी बताया गया है। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के कई छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को अपना समर्थन दिया है। छात्रों का कहना है कि साल भर की मेहनत पर पानी फिरने के बाद अब वे सिर्फ कोर्ट के भरोसे हैं।

दिवशा शर्मा मौत मामला : रिटायर्ड जज सास को हाई कोर्ट का नोटिस, सरकार बोली...जांच में सहयोग नहीं कर रही...

भोपाल/जबलपुर, 25 मई 2026। अभिनेत्री और मॉडल दिवशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब बेहद तेजी से कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। सोमवार को इस मामले में तीन बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपित सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा है। वहीं, मामले की कमान संभालते ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को टीम दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिवशा के पिता नवनिधि शर्मा और राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सरकार और पीडित परिवार ने ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों में कोर्ट में साफ कहा कि आरोपित गिरिबाला सिंह पुलिस जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्हें कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुईं। दूसरी तरफ, गिरिबाला सिंह के वरिष्ठ वकील मुंशी सिंह ने सरकारी दवाओं को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें अभी तक याचिका से जुड़े जरूरी दस्तावेज ही प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। मृतका के पिता के वकील पीयूष सिंह ने बताया कि अदालत ने पूर्व जज को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर यानि 27 मई तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

प्रेमानंदजी की अपील... मैं रहूँ न रहूँ, हमेशा साथ रहूँगा, मेरी चिंता छोड़िए, श्रीजी का ध्यान लगाइए

मधुरा, 25 मई 2026। बिल्कुल चिंता मत करो। हम मिलें न मिलें, बोलें न बोलें, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी। न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। ये भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की। 1 मिनट 19 सेकेंड का वीडियो रिविवा को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 17 मई यानि 9 दिन से प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा- देख लेना तुम वही करोगे, जो गुरुदेव करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो जहाँ जिस सेवा में आए, उस सेवा में रहिएगा। खुद मान जप करो। मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। आप निर्भय, निश्चिंत, निराशंका होकर भजन करो। हमारा जब मन होगा, तब हम बोलेंगे। प्रेमानंद जी ने कहा- हम एकांतवास कर रहे हैं। एकांतवास आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे। हमारे लिए हमारा मन नहीं है। हम आपको सही बताए तो हमारा जो कुछ होगा था, वो हो गया। जो कुछ हो रहा है, वह सब आपके लिए हो रहा है।

इस महीने में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम...

पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा

नई दिल्ली, 25 मई 2026। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब इंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता और खासकर मध्यम वर्ग की परेशानियां बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों, यात्रियों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। लेकिन अब, राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले, 23 मई को कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई थीं।



राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बताया...महंगाई मानव मोदी कल- अभी और बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का दाम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार हुई बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिखा है। उन्होंने एक्स प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मानव मोदी बताया और कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम कितने में बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की जेब चुपके-चुपके कटती रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि अभी दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। राहुल ने एक्स पर लिखा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल-डीजल के दाम कितने में बढ़ाते हैं- ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीने से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदीजी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल 8 रुपये महंगा कर दिया। ये बढ़त होती जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है- चुनाव में वादे, और बाकी समय जनता की जेब पर वार। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार 25 मई को फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिन से भी कम समय में यह चौथी बार है, जब तेल कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं। इस बार पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है।

कांग्रेस बोली...संकट के समय जनता को राहत नहीं दे रही सरकार

कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और तेल कंपनियों के मुनाफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क के जरिए जनता से 43 लाख करोड़ रुपये वसूले, लेकिन आर्थिक संकट के समय लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियों के संयुक्त शुद्ध लाभ में चौथी तिमाही में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रागिनी नायक ने सोमवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल की चुनावी रणधार्मिकता में कह रहे थे कि देश में तेल का कोई संकट नहीं है और महंगाई नहीं बढ़ेगी। गृहमंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यही कह रहे थे कि देश के तेल भंडार पर्याप्त हैं और किसी प्रकार का संकट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यदि स्थिति सामान्य थी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ाए जा रहे हैं।



पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई पर खरबे केजरीवाल ने सरकार पर उठाए सवाल

देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में पिछले एक महीने से भी कम समय में चार बार बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरबे और आम जनता पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। खरबे ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से जनता का जीवन कठिन हो गया है और सरकार के पास इसे रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं है। खरबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और वह नहीं जानता कि तेल के दामों को कितना बढ़ाया जा सकता है। खरबे ने कहा कि सरकार के समय जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बहुत बढ़ी थीं तब भी सरकारी दखल जताकर तेल की कीमतें अलग-अलग सरकारी कम्पनी 90 पैसे, कभी एक रुपये और कभी दो रुपये की बढ़ोतरी कर रही है। जिससे स्पष्ट है कि उनकी अर्थशास्त्रज्ञ संभल नहीं रही है। खरबे ने कहा कि महंगाई से लोग बचते हैं, परंतु तेल के दामों में बढ़ोतरी की जरूरी तीव्र महसूस हो गई है। खरबे की किर और शिवा का खर्च बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने दोस्तों को बेच रही है और रोजगार के अवसर खत्म कर रही है। खरबे ने कहा कि आज जनता दोहरे भार झेल रही है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई।

असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश पारित होने पर बनेगा देश का तीसरा राज्य

गुवाहाटी, 25 मई 2026। असम विधानसभा के चल रहे अधिवेशन के तीसरे दिन सोमवार को सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक सदन में पेश कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में बिल को प्रस्तुत किया। यदि यह बिल पारित होता है, तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद, असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूसीसी कानून लागू करेगा। विधानसभा में विधेयक पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी चर्चा देखने को मिली। माना जा रहा है कि चालू सत्र के दौरान इस विधेयक पर विस्तृत बहस होगी और 27 मई को इसे पारित किया जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 मई को मुख्यमंत्री



हिमंत बिस्वा सरमा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी दी थी। यह बैलक गुवाहाटी स्थित कोइनाधारा के नंबर-1 स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यूसीसी विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा का यह सत्र 21 मई से शुरू हुआ है और 26 मई को समाप्त होगा। सरकार के अनुसार, प्रस्तावित यूसीसी कानून के दायरे से अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजाति (मैदानी) समुदायों को बाहर रखा गया है। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज, प्रथाएं और अनुष्ठान भी इस कानून

से मुक्त रहेंगे। असम सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी मुख्य रूप से चार प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है- शादी की न्यूनतम उम्र तय करना, बहुविवाह पर रोक, पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देना और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों को कानूनी दायरे में लाना। वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि यह विधेयक सामाजिक और पारि वारिक मामलों में एक समान नागरिक व्यवस्था लागू करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 126 सदस्यों वाले सदन में 82 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की। अपने सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के साथ मिलकर 10-10 सीटें जीतीं।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा, टीवीके में हुए शामिल



चेन्नई, 25 मई 2026। तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को तब बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम के तीन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत ही तमिलनाडु वेत्ती कडगम (टीवीके) का दामन ग्रहण किया। मद्रुराई विधायक मरगतम कुमारवल, पेरेन्दुराई विधायक जयकुमार और धारापुरम विधायक सत्यभामा ने विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद तीनों विधायकों ने चेन्नई सचिवालय पहुंचकर लोक निर्माण मंत्री आश्व अर्जुन से मुलाकात की और औपचारिक रूप से टीवीके में शामिल हो गए। मंत्री ने उन्हें शॉल पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और उनसे कुछ देर चर्चा भी की। विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के विधायकों को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, पीट बोली...इतनी भावुकता से न लें

नई दिल्ली, 25 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और उस पर तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। एक वकील ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए सीजेपी से जुड़े व्यक्तियों को गतिविधियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की थी। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्यागमूर्ति जयपाल्य बागची और वीएफ पंचोली की पीठ ने कहा कि इसे इतना भावनात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने सीजेपी के खिलाफ अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट में होने वाली बातचीत का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, अभी ऐसी कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं है। देखते हैं क्या होता है। एक अलग याचिका में आंदोलन से जुड़े

धर्मोन्ड्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने रिसीव किया महिला क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला...

नई दिल्ली, 25 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मोन्ड्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस-सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। महिला क्रिकेट के हीम को कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्डकप जीता था। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, 65 विजेताओं को आगले फेज में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तारीखें अभी

धर्मोन्ड्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने रिसीव किया महिला क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला...



सामने नहीं आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तेवी गुबिन को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश

धर्मोन्ड्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने रिसीव किया महिला क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला...

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुडुचेरी के सिल्लवम (मार्शल आर्ट) खिलाड़ी के. पञ्जनीवेल को पारंपरिक मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूए। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिखला जगदेश कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञापन जगत की जानी-मानी हस्ती दिवंगत पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।

महाराष्ट्र में 800 फीट गहरी खाई में गिरी कार, आठ युवकों की मौत

महाबलेश्वर, 25 मई 2026। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में एक भीषण सड़क हादसे ने आठ लोगों जान चली गई। पोलादपुर-अंबेन्डे घाट मार्ग पर एक स्काईपॉय कार अनियंत्रित होकर करीब 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप में आ गया। सूचना मिलते ही महाबलेश्वर ट्रैफर्स की टीम, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी मृतक सातारा जिले के कोरगांव तहसील के आसगांव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें महेश अन्तल पवार (25), अदित्य अशोक सालुंखे (21), रितेश राजेंद्र लोखंडे (25), सुहृदस जितेंद्र लोखंडे (20), अंश समीर चव्हाण



(18), उत्कर्ष आनंद शिंगे (21), अनिल अभिमन्यू शिंगे (25) नितीन किसन नायकोंडे (35) शामिल हैं। सुवह करीब छह बजे से चार अलग-अलग रेस्क्यू टीमों युद्धस्तर पर बचाव अभियान में जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल दुर्घटना की असली वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि घाट मार्ग के खतरनाक मोड़, रात का समय या वाहन के नियंत्रण खोने जैसी परिस्थितियां हादसे की वजह हो सकती हैं।

महाराष्ट्र के धुले जिले में भीषण सड़क हादसा, छह लोगों की मौत, 26 घायल

महाराष्ट्र के धुले जिले के लालिंग घाट इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं, 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह सड़क हादसा जिले के लालिंग घाट इलाके में सुबह के समय हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा रेत से भरे डंपर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर के कारण हुआ। इस घटना के तुरंत बाद टोल प्लाजा स्टाफ और एक पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को निकालने के काम में लगा गई। इसी दौरान यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस ने ट्रक और डंपर को टक्कर मारी। इस जबरदस्त टक्कर में, पैसेंजर बस के कंठिन में बैठे कई लोगों की तुरंत मौत हो गई। इस हादसे में 20 से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए धुले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हादसे की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा।

फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदेगा भारत, 90 का निर्माण देश में ही होगा

नई दिल्ली, 25 मई 2026। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रही है। इसके लिए अनुरोध पत्र (लौआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही फ्रांस को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इन 114 में से लगभग 90 का निर्माण फ्रांसीसी और भारतीय कंपनी संयुक्त रूप से भारत में ही करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 90 विमानों का निर्माण घरेलू स्तर पर फ्रांसीसी निर्माता डर्बल्ट एविएशन और एक भारतीय कंपनी के बीच सहयोग से मिलकर होगा। वहीं, बाकी विमान उड़ान भरने के लिए तैयार स्थिति में मिलेंगे। रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि फ्रांस के लौआर का जवाब देने के तुरंत बाद भारत खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (आरएफपी) को औपचारिक रूप देगा। भारत सौदे के तहत लगभग 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री शामिल करने



की योजना बना रहा है। साथ ही विमान के इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट हासिल करने पर भी जोर दे रहा है, ताकि स्वदेशी हथियार प्रणालियों जैसे को राफेल में जोड़ा जा सके। हालांकि, विमान के पूरे सोर्स कोड तक पहुंच मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक बातचीत पूरी कर सौदे पर हस्ताक्षर करना है। इस प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 महीने पहले मंजूरी दी थी।

संपादकीय



घुसपैटियों की वापसी

यह अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले एक के बाद एक टोस फैसले लगाता रहे रही है। ऐसा समय की मांग भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासन में कई मोर्चों पर राज्य को एक तरह से पटरी से उतारने का काम किया था। इसे देखते हुए शुभेंदु सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह तेजी के साथ निर्णायक फैसले ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें से कई चुनौतियां ममता सरकार को तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम थीं।

तुष्टीकरण की इन्हीं नीतियों से उपजी समस्याओं से पार पाने के लिए पिछले दिनों शुभेंदु सरकार ने एक ओर जहां मजहबी आधार पर जारी नीतियों को समाप्त करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी ओर कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी टोस कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में उसकी ओर से बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैटियों को चिह्नित करने और उन्हें निकालने के लिए जो कदम उठाने शुरू किए हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। इन कदमों के तहत घुसपैटियों की पहचान कर उन्हें हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में हिरासत केंद्र बनाए जा रहे हैं।

सभी बांग्लादेशी घुसपैटियों को चिह्नित कर उन्हें वापस भेजना आसान काम नहीं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर यह करना ही होगा, क्योंकि एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक है और दूसरे उनकी पहचान करना भी कठिन हो गया है। इसका कारण यह है कि ममता घुसपैटिए फर्जी पहचान पत्र हासिल कर बंगाल के मतदाता बन चुके हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मतदाता बने ये बांग्लादेशी घुसपैटिए राज्य के कई चुनाव क्षेत्रों के परिणाम को प्रभावित करने में उसी तरह समर्थ हो गए थे, जैसे कि असम में हो गए थे।

बांग्लादेशी घुसपैटियों को वापस भेजने के अभियान को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से भी संपर्क-संवाद करना होगा। बांग्लादेश सरकार के सहयोग के बिना अवैध रूप से भारत आए उनके नागरिकों को वापस भेजना कठिन हो सकता है। इस कठिनाई को हल करने का काम केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में बांग्लादेश से कोई घुसपैट न होने पाए।

यह एक तथ्य है कि अभी तक संकीर्ण राजनीतिक कारणों और सच कहा जाए तो वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण बांग्लादेश से होने वाली घुसपैट की अनदेखी ही नहीं हो रही थी, बल्कि एक तरह से उसे बढ़ावा भी दिया जा रहा था। यह सिलसिला दशकों से कायम था। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने भी इस सिलसिले पर विराम नहीं लगाया। उल्टे वह घुसपैटियों के समर्थन में आ खड़ी हुई थीं।

यह कैसा समाज है, जिसमें अदालतें समझाएं रिशतों का धर्म



ललित गार्ग पटपडगंज, नई दिल्ली

कि सी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों, आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, माता-पिता और निर्बल वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन आज का सबसे पीछेदायक प्रश्न यही है कि जिस भारत ने मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः का उद्घोष किया, जिस धरती से वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार पूरी दुनिया में पहुँचा, उसी भूमि पर आज माता-पिता को अपने ही घर में सम्मान और आश्रय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में देश की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जहाँ वृद्ध माता-पिता को अपने ही बच्चों से संरक्षण, भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार के लिए न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ा। कहीं बेटे को अदालत यह निर्देश दे रही है कि वह अपने वृद्ध मां को घर में एक कमरा, अलग खानाघर और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराए, तो कहीं दुर्व्यवहार करने वाली संतान को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह केवल कानूनी घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारे

सामाजिक और नैतिक पतन की वे चेतवनियाँ हैं जो भविष्य के भारत की तस्वीर पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। वास्तव में यह अत्यंत विडम्बनापूर्ण है कि जिस मां ने नौ महीने गर्भ में रखकर संतान को जीवन दिया, जिसने अपना रक्त, ममता और त्याग देकर उसे पाला, उसी मां को अपने ही घर में रहने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जिस पिता ने अपने पसीने और परिश्रम से घर बनाया, बच्चों का भविष्य संवार, वृद्धावस्था में उसी घर में उसके अधिकार के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, यह स्थिति केवल व्यक्तिगत कुतन्त्रता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं के क्षरण का प्रमाण है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, स्मार्ट शहर, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। लेकिन यदि घर के किसी कोने में बैठे वृद्ध माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहे हों, तो क्या यह विकास पूर्ण माना जा सकता है? यदि हमारे बुजुर्ग अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं, और उपेक्षित हो जायें, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ खोखली प्रतीत होती हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्भरता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गईं हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिशतों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं। परिणामतः बुजुर्गों का जीवन अकेलेपन, अवसाद और असुरक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। यह सत्य है कि महानगरीय जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। रोजगार, समयाभाव, आर्थिक दबाव और



बदलती जीवनशैली ने नई पीढ़ी की चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद माता-पिता के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य रही है। श्रवण कुमार का आदर्श केवल कथा नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का हिस्सा है। दुर्भाग्य यह है कि आज संपत्ति और स्वार्थ ने अनेक संबंधों को प्रभावित किया है। अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार दिखाई देते हैं जिनमें संपत्ति के लिए माता-पिता को प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मानसिक यातना दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक वृद्धाश्रम ऐसे माता-पिता से भरे पड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी गलती केवल यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी। यदि यह प्रवृत्ति यून ही बढ़ती रही तो भारत भी उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पश्चिमी देशों की तरह माता-पिता और संतान के संबंध केवल कानूनी और औपचारिक होकर जा रहे हैं। पश्चिमी समाज में अनेक माता-पिता प्रार्थन से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं क्योंकि वे भविष्य में उनसे देखभाल की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन भारतीय समाज को आधार इससे भिन्न रहना है। यहाँ परिवार केवल जैतिक इकाई नहीं, बल्कि

भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था रहा है। यह भी स्मरणीय है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 जैसे कानून बनाए गए हैं ताकि वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर माता-पिता के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखा है और दुर्व्यवहार करने वाली संतानों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियाँ भी की हैं। लेकिन कानून केवल सुरक्षा दे सकता है, संवेदना नहीं। अदालतें कर्मरे दिला सकती हैं, सम्मान नहीं, भरण-पोषण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन ममता और अपनत्व नहीं लाती सकती। यही कारण है कि समाधान केवल कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। परिवारों में संस्कारों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। बच्चों को केवल उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएँ देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्य भी देना होगा। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को परिवार, सेवा, कृतज्ञता और बुजुर्ग सम्मान जैसे विषयों पर गंभीर पहल करनी चाहिए।

आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में वृद्ध सम्मान को भी एक महत्वपूर्ण सूचक बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट

होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकता है। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता-पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकती। माता-पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है। यह भी विचारणीय है कि जो संतान आज अपने माता-पिता के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार भविष्य में उसके हिस्से भी आ सकता है। बच्चे केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे अपने माता-पिता को बुजुर्गों की उपेक्षा करते देखेंगे तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे।

आज आवश्यकता अदालतों के आदेशों से अधिक अंतःकरण के जागरण को है। रिशतों की मर्यादाएँ, गरिमा और दायित्व यदि न्यायालयों को समझाने पड़े तो यह केवल कानूनी संकेत नहीं, बल्कि सभ्यता का संकेत है। यह समय आत्ममंथन का है कि क्या हम तकनीकी रूप से आधुनिक होते-होते मानवीय रूप से निर्धन होते जा रहे हैं? भारत की पहचान उसकी संवेदनशीलता रही है। यदि हम इस संवेदनशीलता को बचा सके, तभी विकसित भारत का स्वप्न सार्थक होगा। अन्यथा ऊँची उपलब्धियों और भव्य योजनाओं के बीच भी हमारे घरों के किसी कोने में बैठा एक उपेक्षित वृद्ध हमारी समस्त प्रगति पर मौन प्रश्नचिह्न बनकर खड़ा रहेगा। अंततः याद रखना होगा-हिरासत संपत्ति नहीं, संस्कार होते हैं, विकास इमारतों से नहीं, रिशतों से मापा जाता है। कहलाता कभी ममान नहीं और हलता जहाँ माता-पिता को अपने अधिकार के लिए अदालतों में खड़ा होना पड़े।

ब्रिटेन से लौट रही भारतीय विरासत जैन पांडुलिपियों की ऐतिहासिक घर-वापसी



ज्योति जैन आगरा, उत्तरप्रदेश

भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति, ज्ञान परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों से होती है। सदियों पुरानी पांडुलिपियाँ, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे गौरवाशाली अतीत के जीवंत प्रमाण हैं। किंतु दुर्भाग्यवश भारत की इस ज्ञान समृद्ध को विभिन्न देशों द्वारा समय-समय पर लूटा गया। पिछली सदियों में भारत की अनेक दुर्लभ धार्मिक और ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ यूरोप के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संस्थानों तक पहुँचने लगीं। उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान कई विदेशी विद्वान, शोधकर्ता और संग्रहकर्ता भारतीय ग्रंथों को अध्ययन और संरक्षण के नाम पर अपने साथ ले गए। इन्हीं में जैन धर्म से संबंधित हजारों पांडुलिपियाँ भी शामिल थीं, जिन्हें 20 वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन ले जाया गया और बाद में लंदन के प्रसिद्ध वेल्कम कलेक्शन में संरक्षित कर लिया गया।

ऐसे में ब्रिटेन के प्रसिद्ध 'वेल्कम कलेक्शन' द्वारा जैन समुदाय को 2,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों को वापस लौटाने

का निर्णय भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है। लगभग एक सदी से भी अधिक समय से लंदन में सुरक्षित रखी गई ये पांडुलिपियाँ अब अपने मूल समुदाय तक पहुँचने जा रही हैं। यह केवल प्राचीन दस्तावेजों की वापसी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, ऐतिहासिक गौरव और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। इस निर्णय ने न केवल जैन समुदाय, बल्कि पूरे देश को गर्व और संतोष का अनुभव कराया है।

इन पांडुलिपियों का संग्रह अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य माना जाता है। इनमें 15 वीं से 19 वीं शताब्दी तक के धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथ शामिल हैं। प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पुरानी हिंदी जैसी भाषाओं में लिखे गए ये दस्तावेज भारतीय ज्ञान-विज्ञान और दर्शन की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ 'कल्पसूत्र' की सुंदर चित्रित प्रतियाँ भी इस संग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, नैतिकता और सामाजिक जीवन से जुड़े अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी इसमें सुरक्षित हैं।

इन पांडुलिपियों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत व्यापक है। कई दस्तावेज ऐसे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विचारों तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना को उजागर करते हैं। इन ग्रंथों में निहित नैतिक मूल्यों को मानवीय विचारों ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को भी प्रभावित किया था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस ऐतिहासिक पहल के पीछे लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेलॉजी और वेल्कम कलेक्शन के बीच हुआ सहयोग महत्वपूर्ण है। समझौते के तहत इन पांडुलिपियों को प्रारंभ में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के 'धर्मनाथ नेटवर्क इन जैन स्टडीज' में संरक्षित किया जाएगा, जहाँ विशेषज्ञ इनके अध्ययन, अनुवाद और संरक्षण का कार्य करेंगे। इससे शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और इतिहासकारों को भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेलॉजी के प्रबंधन्यासी मेहुल संज्ञानका ने इस निर्णय को सांस्कृतिक सहयोग का नया मॉडल बताया है। उनका कहना है कि यह कदम केवल धरोहरों की वापसी नहीं, बल्कि अपने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। वास्तव में, आज के आधुनिक और तकनीकी युग में अपनी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय विश्वभर के संग्रहालयों और संस्थानों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा। इससे अन्य देशों में सुरक्षित भारतीय धरोहरों की वापसी के लिए भी सकारात्मक वातावरण तैयार हो सकता है। साथ ही यह संदेश भी मजबूत होगा कि किसी भी देश की सांस्कृतिक संपत्ति उसी देश और समाज की आत्मा होती है।

अंततः कहा जा सकता है कि जैन पांडुलिपियों की यह ऐतिहासिक घर-वापसी केवल अतीत की स्मृतियों को लौटाने का प्रयास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल अपने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ते हुए भारतीय सभ्यता के गौरव को और अधिक सशक्त बनाएगी।

स्वयं के प्रति क्रूरता तथा कठोरता श्रेष्ठ होने के प्रमुख अवयव



संजीव ठाकुर रायपुर, छत्तीसगढ़

मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। अक्सर हम दुनिया को बदलने, समाज को सुधारने और दूसरों को सही ठहराने में लगे रहते हैं, परंतु एक सत्य हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है यदि हमने स्वयं को नहीं जीता, तो हमने कुछ भी नहीं जीता। पहले स्वयं को जीतिए, फिर जग को जीतिए, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। क्योंकि मनुष्य का मन ही उसके किए हुए कार्यों का सर्वोच्च निर्णायक होता है। यदि मन के भीतर ईमानदारी नहीं है, तो बाहरी सफलता भी खोखली प्रतीत होती है। मनुष्य को स्वयं के प्रति अत्यंत कठोर तथा क्रूर होना होगा तभी सफलता उसके सामने होगी।

महात्मा गांधी ने कहा था, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह कथन हमें स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तक हम अपने विचारों, अपनी विरासत, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ते हुए भारतीय सभ्यता के गौरव को और अधिक सशक्त बनाएगी।

बनकर रह जाती है। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन पहले स्वयं किया, तभी वे करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने।

इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का यह विचार भी अत्यंत प्रेरणादायक है: उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन आज लक्ष्य की प्राप्ति की पहली शर्त क्या है? स्वयं के भीतर की कमजोरी, आलस्य और भ्रम पर विजय प्राप्त करना। विवेकानंद जी ने युवाओं को यह सिखाया कि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना भ्रम, उसकी अपनी असत्यता होती है। जब हम स्वयं से झूठ बोलते हैं अपने दोषों को छिपाते हैं, अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं तब हम अपने विकास के मार्ग को स्वयं ही अवरुद्ध कर देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु खुद ही अपने दीपक बनिए। इसका अर्थ यही है कि आत्मचिंतन और आत्मसत्य ही वह प्रकाश है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। यदि हम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करेंगे, तो प्रकाश की खोज भी अधूरी रह जाएगी। समाज में श्रेष्ठ और महान लोग वही बने हैं, जिन्होंने पहले स्वयं को जीत लिया।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन इसका सर्वोच्च उदाहरण है। एक साधारण परिवार से उत्कटर देश के सर्वोच्च पद तक



पहुँचना केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी आंतरिक अनुशासन, ईमानदारी और आत्मविश्वास का फल था। उन्होंने कहा था, अपने मन को नहीं हम सोते समय देखते हैं, अपने मन को हमें सोने नहीं देते। यह सपना तभी साकार होता है, जब हम अपने भीतर की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का साहस रखते हैं।

इसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में 27 वर्ष जेल में बिताए, परंतु उन्होंने अपने भीतर की नफरत को जीत लिया। उन्होंने कहा था, मैं कभी हारता नहीं था, तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। यह दृष्टिकोण केवल वही व्यक्ति अपना सकता है, जिसने स्वयं को साध लिया हो। मंडेला की यह आंतरिक विजय ही उन्हें एक महान नेता बनाती है।

जब हम समाज में देखते हैं, तो पाते हैं कि जो लोग ईमानदारी, सच्चाई और आत्मसंयम के मार्ग पर चलते हैं, वही सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है, सफलता वह शांति है, जो हमें अपने भीतर मिलती है। यदि हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, तो दुनिया की कोई भी प्रशंसा हमें संतुष्ट नहीं कर सकती।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन के सामने सच्चे रहें।

आज के समय में, जब प्रतिस्पर्धा और दिखावे की होड़ बढ़ती जा रही है, तब स्वयं से सत्य बोलना और भी कठिन हो गया है। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक ऐसा चेहरा बना लेते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं होता। लेकिन यह दिखावा अधिक समय तक नहीं टिकता। अंततः हमें अपने भीतर लौटना ही पड़ता है, और वहीं हमारा असली सामना होता है। यदि हम उस क्षण में स्वयं को सच्चा पाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है।

इसलिए, हमें यह समझना होगा कि जीवन की असली दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि स्वयं से बेहतर बनने की है। हर दिन अपने भीतर की कमियों को नजरअंदाज करने का साहस रखते हैं।

अंत में, यही कहना उचित होगा कि स्वयं की जीत ही सच्ची विजय है। जब मनुष्य अपने मन, अपने विचारों और अपने कर्मों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है।

तो आइए, हमें संकल्प लें कि हम स्वयं से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, और निरंतर आत्मसुधार के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि जब हम स्वयं को जीत लेते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यही जीवन का सार है पहले स्वयं को जीतिए, फिर जग को।

समाज की सशक्त प्रहरी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत सामाजिक कार्यकर्ता हिरा देवी निराला

छत्तीसगढ़ महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित हिरा देवी निराला डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान और डॉ भीमराव अंबेडकर विरासत सम्मान से सम्मानित हैं...

लक्ष्मीनारायण लहरे धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर समाज में प्रथम पुत्र के रूप में श्रीगणेश जी को पूजे जाते हैं। परिवार और समाज में अग्रणीय सबसे जिसका ऊंचा दर्जा होती है वह माँ की होती है। माँ शब्द संसार की वो सबसे बड़ी शब्द होती है जो जीवन का पालनहार होती है, जो जीवन का पालनहार होती है, जो तपस्या को शब्दों से बयां कर पाना संभव नहीं है माँ वह भाषा है जिसे छोटा बच्चा दूध पीते हुए आंचल में छुपकर बड़ा होता है और अपना जीवन उसके माँ छया में पनपता है। माँ वह अबुद्ध पहली है जो जीवन को संवारी है स्वच्छ समाज गढ़ती है। माँ सृजन की पटशाला है वह खुद तपकर -त्याग और समर्पण से समाज को गढ़ती है। शिक्षाविद् सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती

हिरा देवी निराला की जीवन कशमकश सही रहों से गुजरते हुए समाज को नई सीख देती है जो समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है। हिरा देवी बचपन से ही होनहार विद्यार्थी रही समाज के प्रति उनका लगाव रहा। आज उन्हें समाज की सशक्त प्रहरी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप लोग अब जानने लगे हैं उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों से सारंगढ़ - बिलाईगढ़ जिला का नाम गौरवान्वित कर समाज को नई संदेश दे रहे हैं। उनका जन्म 15 जून 1969 को हुआ वे सामाजिक विज्ञान में एम ए हैं। सारंगढ़ जिला मुख्यालय में प्रॉजल विशेष स्कूल दिव्यांगजन स्कूल संचालित करती हैं। इस स्कूल की स्थापना 2006 में हुई पिछले 19 वर्षों से ऐसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं जो

समाज से सीधा सीधा टूटे हुए होते हैं जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते उनके बीच रहकर उनकी सेवा के साथ साथ पढ़ना लिखना और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चुनौती भरा कार्य है ऐसे बच्चों के परिवार भी उनसे दूरी रखते हैं ऐसे बच्चों की देख भाल माता पिता की तरह करना गारर में सागर भरने जैसा कार्य है दिव्यांग बच्चों गढ़ना चुनौती भरा है। उनकी इस सामाजिक



कार्य एवं सेवा भाव को लेकर उन्हें रायपुर की अग्रणीय सामाजिक व साहित्यिक संस्था वका मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ महिला गौरव अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वे कई मंचों से सम्मानित हुई हैं। अपने जीवन के ज्यादा समय सामाजिक कार्यों में गुजरते हैं। उनकी यह कार्य समाज के लिए प्रेरणा योग्य है। उनकी कार्य अखबारों के पत्रों से भले ही दूर हैं पर उनके कार्य सराहनीय हैं। जो समाज को

नई राह दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसमें सारंगढ़ - बिलाईगढ़ जिला से सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हिरा देवी निराला का भी एक नाम था। अपने उत्कृष्ट कार्यों से सम्मानित होती रही हैं। वर्ष 2025 में कई सम्मान से सम्मानित हुई हैं इसके पूर्व भी वे नारी सशक्तिकरण के लिए सम्मानित हुई हैं। दिव्यांगजन विशेष स्कूल की संरक्षक के साथ साथ वृद्ध सदन की भी जिम्मेदारी है। वही विशेष स्कूल में 40 बच्चों की वह माँ है उनके साथ रहकर उन्हें उनकी जीवन गढ़ रहे हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रॉजल विशेष स्कूल के अलग अलग पहचान है जहाँ लोगों की विश्वास जुड़ी है। वहाँ संचालिका नहीं एक माँ रहती है जो

समाज को नई दिशा दे रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हिरा देवी निराला अपनी कार्यों से पहचानी जाती हैं जो समाज के लिए एक मिशाल से कम नहीं है। वे अब तक कई मंचों से सम्मानित हुई हैं हाल ही में डॉ भीमराव अंबेडकर विरासत सम्मान 2026 से सम्मानित हुई हैं इसके पूर्व डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान यही नहीं वे मिनीमाता जयंती पर नारी सशक्तिकरण सम्मान, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला गौरव सम्मान 2026, नई पीढ़ी की आवाज, तुलसी साहित्य अकादमी विभिन्न मंचों से सम्मानित हुई हैं। वे समाज के लिए एक प्रहरी के रूप में जानी जाती हैं। उनके समाजिक कार्यों के लिए वे पहचानी जाती हैं।

सूचना समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा। -सम्पादक-

बिजली व्यवस्था पर मंडराया संकट! तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

12 हजार से अधिक स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा खाली, फाल्ट सुधार से लेकर स्मार्ट मीटरिंग तक प्रभावित, दुर्घटनाओं का भी बढ़ा खतरा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था में तकनीकी (लाइन) कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द रिक्त पद नहीं भरे गए तो प्रदेश की बिजली व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। संघ के प्रांतीय महासचिव दीपक कुमार निकुंज द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में विद्युत वितरण व्यवस्था में तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। लाइन स्टाफ के कुल 12,317 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 5,747 नियमित कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जबकि 6,570 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यानी आधे से अधिक पद खाली हैं।

कर्मचारियों पर बढ़ा अत्यधिक कार्यभार

अभियंता संघ ने कहा कि कम स्टाफ होने के कारण एक ही कर्मचारी से कई प्रकार के कार्य लिए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है और दुर्घटनाओं की संभावना भी लगातार बनी रहती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवश्यक संधारण और रखरखाव कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर कंपनी की कार्यप्रणाली के साथ-साथ शासन और प्रशासन की छवि पर भी पड़ रहा है।

शासन के कार्यक्रम भी हो रहे प्रभावित

संघ ने मुख्यमंत्री को बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण शासन द्वारा आयोजित शिविरों और जनसमस्या निराकरण कार्यक्रमों में भी समयबद्ध कार्य निष्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है।

फाल्ट सुधार और बिजली बहाली में हो रही देरी : ज्ञापन में कहा गया है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण लाइन फाल्ट और ब्रेकडाउन सुधार कार्यों में लगातार देरी हो रही है। बिजली आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लगने से उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। विभाग को लगातार शिकायतें और पत्राचार प्राप्त हो रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। संघ का कहना है कि सीमित कर्मचारियों से लगातार कई तरह के कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं।

को लगातार शिकायतें और पत्राचार प्राप्त हो रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। संघ का कहना है कि सीमित कर्मचारियों से लगातार कई तरह के कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं।

स्मार्ट मीटरिंग और ई-सेवाओं पर भी असर : ज्ञापन में कहा गया है कि पर्याप्त तकनीकी एवं फील्ड स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण स्मार्ट मीटरिंग कार्य, समय पर इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग और E-SEAM जैसी सेवाओं का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। नई तकनीकों और योजनाओं को जमीन पर लागू करने में विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आउटसोर्स कर्मचारियों से कराए जा रहे जोखिम भरे काम : संघ ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में आउटसोर्स कर्मचारियों से बिजली पोल पर चढ़कर कार्य कराया जा रहा है, जबकि नियमानुसार वे ऐसे कार्य करने के पात्र नहीं हैं। अभियंता संघ ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराना न्यायविरुद्ध नहीं होगा।



मुख्यमंत्री से शीघ्र भर्ती की मांग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, ताकि विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ताओं को समय पर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि यदि इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो राज्य की विद्युत वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है और आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

दो सड़क हादसों में 6 की मौत, ट्रैक्टर चालक घायलों को छोड़ इंजन लेकर फरार बलरामपुर में 4 युवकों की गई जान, लखनपुर में कार की टक्कर से चाचा-भतीजा की मौत



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर और सरगुजा जिले में रविवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के समाल रोड स्थित पीपरपान गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। इसके बाद घायलों को सड़क पर छोड़ ट्रॉली से इंजन निकालकर फरार हो गया। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार चाचा-भतीजा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार समाल निवासी रमेश पण्डे (19), मनोज पण्डे (21), नरेश पण्डे (19) और रमेश पण्डे (17) रविवार शाम डंडो बाजार से एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। शाम करीब 6.30 बजे पीपरपान गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक प्रेमचंद यादव बाइक सवारों को करीब 100 मीटर तक घसीटते ले गया। हादसे के बाद चालक ने वाहन में फंसे युवकों को सड़क पर छोड़ दिया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के बजाय ट्रॉली से इंजन निकालकर मौके से फरार हो गया। राश्रीयों की मदद से चारों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि चालक समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाता तो किसी की जान बच सकती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि चालक इंजन को अपने ससुराल बगम में छिपाकर फरार हो गया है। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

लखनपुर में कार की टक्कर से चाचा-भतीजा की मौत

इधर, दरिया थाना क्षेत्र के महुआटिका निवासी रामकुमार सिंह (65) अपने भतीजे जय सिंह के साथ रिश्तेदारी में आयोजित प्रीतिभोज से लौट रहे थे। रात करीब 9.30 बजे लखनपुर थाना क्षेत्र के जजगा गांव स्थित रामपुरहीन माता मंदिर के पास पीछे से आ रही कार क्रमोंक सीजी 11 बीटी 7498 ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर रूप से घायल चाचा-भतीजा को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

तेज रफ्तार और लापरवाही बन रही हददसों की वजह

अम्बिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर गति नियंत्रक और चेतावनी संकेत नहीं होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से नवापारा अस्पताल को मिली नई ताकत, मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया लोकार्पण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थल मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोमवार को नवापारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवीन ऑपरेशन थियेटर का लोकार्पण एवं अतिरिक्त वार्ड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। जिला चिकित्सक न्यास निधि से निर्मित इस स्वास्थ्य परियोजना को क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा DMF फंड का उपयोग जनहित के कार्यों में प्राथमिकता से किया जा रहा है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त वार्ड शुरू होने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा और गंभीर स्थिति में बड़े अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुषा सिंह, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह (टि.नि.), कलेक्टर अजीत वसंत, जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल एवं नगर निगम आयुक्त डी.एन. करण सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

विश्रामपुर SECL में हरियाली पर आरी! कभी राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाला क्षेत्र अब उजड़ने की कगार पर

हजारों पेड़ों की कटाई के आरोप, अधिकारियों-दलालों की मिलीभगत की चर्चा, बढ़ती गर्मी के बीच पर्यावरण संरक्षण पर उठे गंभीर सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में बढ़ती गर्मी, सूखते जलस्रोत और लगातार घटती हरियाली के बीच विश्रामपुर SECL क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सुर्खियों में आ गया है। जिस क्षेत्र को कभी उत्कृष्ट वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला था, वहीं अब हरियाली उजड़ने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि विश्रामपुर क्षेत्र में वर्षों पहले लगाए गए हजारों वृक्षों को सुनियोजित तरीके से काटा जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही पोस्टों और स्थानीय चर्चाओं के बाद यह मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों, दलालों और संरक्षण प्राप्त लोगों की मिलीभगत से हरे-भरे वृक्षों को काटकर लकड़ी का कारोबार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी जिम्मेदार विभाग की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कभी हरियाली की पहचान था जयनगर मोड़ क्षेत्र...

स्थानीय नागरिक बताते हैं कि अम्बिकापुर से विश्रामपुर जाने वाले मार्ग पर जयनगर मोड़ के आसपास स्थित ऊंचे-ऊंचे टोले कभी घने वृक्षों और हरियाली से ढके रहते थे। कोयला उत्खनन के बाद पर्यावरण की



नियमों के तहत SECL विश्रामपुर कोलियरी द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया था। वर्षों की मेहनत से यह क्षेत्र हराभरा बना और प्रदूषण नियंत्रण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्रामपुर कोलियरी के इसी प्रयास को देखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में 'इंद्रा प्रियदर्शी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट कार्य किया हो। उस समय विश्रामपुर क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण का मॉडल माना जाता था।

सिर्फ उद्योगों को दोष देना पर्याप्त नहीं : स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरगुजा में बढ़ती भीषण गर्मी के लिए केवल उद्योगों या बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं



स्थानीय लोगों का कहना है कि आज वही क्षेत्र तेजी से उजड़ता नजर आ रहा है। जहां कभी घने पेड़ और हरियाली दिखाई देती थी, वहां अब पेड़ों के कटे हुए टुकड़े नजर आने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र की हरियाली समाप्त की जा रही है और इसकी आड़ में लाखों रुपए का खेल चल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर किसी सामान्य ग्रामीण द्वारा एक पेड़ काटा जाए तो वन विभाग और प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है, लेकिन बड़े स्तर पर हो रही कटाई के बावजूद जिम्मेदार विभाग मौन क्यों है, यह बड़ा सवाल है।

जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। उनका कहना है कि संभाग में कहीं वनाधिकार पट्टों के नाम पर तो कहीं भू-माफियाओं और अवैध कब्जों के कारण जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं। विश्रामपुर क्षेत्र को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए लोगों ने कहा कि यदि समय रहते हरियाली बचाने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संकट और गंभीर हो जाएगा।

अब हरियाली की जगह दिखा रहे टुकड़े...

वर्तमान प्रबंधन पर भी उठे सवाल : लोगों ने SECL विश्रामपुर क्षेत्र के वर्तमान प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्व अधिकारियों ने वर्षों मेहनत कर हजारों पेड़ लगाए, लेकिन वर्तमान में उन्हीं पेड़ों को काटवाकर मुनाफा कमाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने पूछा कि वर्तमान अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में कितने नए वृक्ष लगाए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए

गंगा दशहरा पर विशेष...

सतरंगी सरगुजा : जहां 'कमल दल' में उतरती हैं गंगा मैया अनोखा है यहां का 'कठपुतली ब्याह' और 'दसराहा' मेला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

भारत में गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जीवनदायिनी मानकर पूजा जाता है। इनमें देव नदी गंगा का स्थान भारतीय जनमानस में सर्वोपरि है। इसी धार्मिक आस्था और लोक-संस्कृति का अनूठा संगम गंगा दशहरा को सरगुजा अंचल में देखने को मिलता है, जहां पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ 'गंगा दशहरा' का पर्व और भव्य दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। भारत में गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाली 'प्राणदायिनी' माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के दिल छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में गंगा मैया को अपने ही गाँव के तालाब में उतार लेने की एक बेहद खूबसूरत और अनूठी परंपरा है? जी हाँ, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की कौड़ी को यहाँ मनाया जाने वाला 'गंगा दसराहा' सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जल संरक्षण, लोक संस्कृति, मनोरंजन और मानवीय संवेदनाओं का एक अद्भुत उत्सव है।

मगीरथ की तपस्या और प्रकृति का उत्सव

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, राजा भीमरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या कर देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुए इसी पावन अवतरण की याद में गंगा दशहरा मनाया जाता है। राज्यपाल पुरस्कृत पद्ममाला पुनलाल बख्शी स्मृति पुरस्कार प्राप्तकर्ता साहित्यकार अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सरगुजा वासियों की यह अदृष्ट आस्था है कि गंगा दशहरे के दिन मैया दूर हिमालय से आकर उनके गाँव के उस जलाशय



में विराजती है, जहाँ पुरान (कमल) के पते खिले होते हैं। ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि 'गंगा जी बहुत दूर हैं, इसलिए हम अपने गाँव के तालाब को ही गंगा तुल्य मानकर पूजते हैं और पुण्य कमाते हैं।' यह अदृष्ट विश्वास है यहाँ के ग्रामीणों का।

इस दिन साल भर के शुभ कार्यों के प्रतीक : जैसे शादी का मोर, कंगन, कलश और यहाँ तक कि बच्चे के जन्म के समय की नाल व छत्री के बाल को गाँव के बैगा (पुरोहित) की मौजूदगी में पूरे विधि-विधान से तालाब में विसर्जित (सेराना) किया जाता है। बच्चे की नाल को कमल की जड़ के नीचे गाड़ा जाता है, जो जल और जीवन के गहरे अंतर्संबंध को दर्शाता है।

जब गुड्डा-गुड्डिया का रचाते हैं ब्याह : इस त्योहार का सबसे अनोखा और कौतुक जगाने वाला हिस्सा है कठपुतली विवाह। प्राचीन मनोरंजन की यह विधा यहाँ की कुंवारी लड़कियों के लिए परंपरा सीखने का जरिया है। लकड़ी से बने गुड्डा-गुड्डिया का ब्याह पूरे तीन दिनों तक चलता है।

निभाई जाती है शादी की रस्में

मड़वा (मंडप) गाड़ने से लेकर विदाई तक, शादी की हर रस्म बड़े-बुजुर्गों की देखरेख में हूबहू निभाई जाती है। गाँव की लड़कियाँ दुल्हन की माँ और लड़के दुल्हे के पिता बनते हैं। इसका मकसद बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना है। दशहरे के दिन इन कठपुतली दुल्हा-दुल्हन को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है।

दान-पुण्य और सामाजिक समरसता की अनूठी परंपरा

सरगुजा अंचल में गंगा दशहरा मनाने का ढंग बेहद खास और अनूठ है। इस दिन यहाँ दान-पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है। मेले और अनिष्ट-संबंधियों को आदरपूर्वक घर पर निर्मान किया। परंपरा के अनुसार, अनाथों को तेल, कपड़े, रोटी और यथाशक्ति नकद राशि दान स्वरूप भेंट की गई और उन्हें सभ्य दशहरा मेला घूमने के लिए प्रेरित किया गया।

पड़ोसियों ने ही उड़ाए जेवर और बाइक

कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को दबोचा, सोना-चाँदी और बाइक बरामद



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के बीरोतालबाब क्षेत्र में सूने मकान में चोरी करने वाले दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के पड़ोसी ही निकले। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चाँदी के आभूषण, नगदी और चोरी गई पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बीरोतालबाब काली मंदिर के पास रहने वाली फूलेश्वरी कुजूर 20 मई को अपने बेटे के साथ जमशेदपुर गई थीं। 23 मई को लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और बालकनी के पास का दरवाजा टूटा हुआ था। जांच में घर से सोने का मंगलसूत्र, नाक का नग, चाँदी की पायल, चाँदी का सिक्का, नगदी और पैशन प्रो बाइक गायब मिली। मामले की शिकायत पर कोतवाली थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मिली कि पड़ोसी संजय पटेल और अभिषेक चेरवा अचानक काफी पैसे खर्च कर रहे हैं और सोना-चाँदी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे उन्होंने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के मंगलसूत्र, लॉकेट, टप्प, चाँदी की पायल, नगदी राशि और चोरी गई पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक चेरवा (24) और संजय पटेल (35) शामिल हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, एसआई देवनायराय यादव सहित कोतवाली पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।

सुशासन तिहार में फूटा अपनों का दर्द... पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले... 'न घोषणा हुई, न समाधान, फिर कैसा सुशासन?

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद गरमाई सियासत

-संवाददाता-

कोरिया, 25 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुशह में आयोजित 'सुशासन तिहार' अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अचानक दौरे और चौपाल कार्यक्रम के बाद अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नजर आए वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान भाजपा के भीतर की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने साय सरकार और स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है।



असहज हो गया जब भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, उन्होंने खुलकर शिकायत करते हुए कहा कि क्षेत्र की भाजपा विधायक जनता और कार्यकर्ताओं से दूर रहती हैं तथा लोगों की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है, भाजपा पदाधिकारी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी, विपक्ष ने इसे सरकार



के 'सुशासन मॉडल' पर सवाल खड़े करने वाला बयान बताया, स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज हो गई कि यदि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ही नाराज हैं, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

गुलाब कमरो का हमला...सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट चल रहा...

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मुख्यमंत्री के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे कार्यक्रम में केवल दिखावा ज्यादा और समाधान कम नजर आया, उन्होंने कहा कि सोनहत क्षेत्र की जनता को इस दौरे से कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, कमरो ने तंज कसते हुए कहा बड़ी घोषणाएं तो दूर, मुख्यमंत्री छोटी सी सौगात तक देकर नहीं गए, न पंचजल संकट का स्थायी समाधान हुआ, न विकास को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई, फिर आखिर इसे सुशासन कैसे कहा जाए? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल प्रचार और कार्यक्रमों के जरिए माहौल बनाने में लगी हुई है, जबकि जमीनी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

सुशासन का गुब्बारा खुद भाजपा ने फोड़ा

गुलाब कमरो ने कहा कि भाजपा सरकार जिस 'सुशासन' का दावा कर रही है, उसकी सच्चाई अब उनके अपने ही कार्यकर्ता उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने भाजपा पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत यह साबित करती है कि क्षेत्र में अंदरूनी असंतोष गहराता जा रहा है, कमरो ने आरोप लगाया कि कोरिया जिले में आज भी लोग बिजली, पानी, सड़क और आवास जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय चौपाल और आयोजनों के जरिए राजनीतिक संदेश देने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है।

चौपाल के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

मुख्यमंत्री के अचानक दौरे और चौपाल के दौरान दिए गए निर्देशों को भाजपा सरकार 'सरकार आपके द्वार' मॉडल के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे 'इवेंट आधारित राजनीति' करार दे रहा है, कुशहा चौपाल के बाद अब जिले की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, एक तरफ सरकार इसे संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यदि समस्याएं इतनी गंभीर हैं, तो अब तक उनका समाधान क्यों नहीं हुआ, फिलहाल इतना तय है कि कुशहा का यह चौपाल केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने सत्ता और संगठन दोनों के भीतर की हलचल को भी खुलकर सामने ला दिया है।

करंट का कनेक्शन या कमीशन का कलेक्शन?

मनेंद्रगढ़ बिजली विभाग में ACB की रेड, जेई और लाइनमैन रिश्त लेते धराए

बिजली कनेक्शन के नाम पर 'करंट टैक्स' वसूलने का खेल बेनकाब



-संवाददाता- मनेंद्रगढ़, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ में बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्त लेने का मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। Anti Corruption Bureau की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) मनीष कुमार बजाज और लाइनमैन राकेश शुक्ला को रिश्त लेते री रो हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डोमनापारा निवासी रमेश सिंह ने अपने घर में बिजली कनेक्शन के लिए

आवेदन दिया था। आरोप है कि कनेक्शन लगाने के बदले जेई और लाइनमैन ने 10 हजार रुपये की मांग की। दोनों ने कहा कि घर तक लाइन खींचने और कनेक्शन देने में 'खर्च' आता है, इसलिए पैसा देना पड़ेगा। सरकारी दफतरी में आम आदमी अक्सर मजबूरी में रिश्त देकर चुप हो जाता है, लेकिन इस बार रमेश सिंह ने हिम्मत दिखाई और मामले की शिकायत अम्बिकापुर स्थित एसीबी कार्यालय में कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरी योजना तैयार की। टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची और शिकायतकर्ता को रिश्त की रकम लेकर

आरोपियों के पास भेजा गया। जैसे ही रमेश सिंह ने 9 हजार 500 रुपये की राशि जेई मनीष कुमार बजाज को दी, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने तत्काल दृष्टि देकर उसे री रो हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान लाइनमैन राकेश शुक्ला को भी हिरासत में लिया गया। रेड के बाद बिजली विभाग कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एसीबी अधिकारियों ने विभागीय दस्तावेजों की जांच की और सहायक अभियंता से भी पूछताछ की। गिरफ्तार दोनों कर्मचारियों को आगे की कार्रवाई के लिए अम्बिकापुर ले जाया गया है। यह मामला

एक बार फिर सरकारी विभागों में व्याप्त रिश्तखोरी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस विभाग का काम लोगों के घरों तक उजाला पहुंचाना है, वहीं अंतर सुविधा के बदले 'कमीशन' मांगा जाए तो आम जनता का भरोसा कमजोर होना तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कनेक्शन, मीटर और लाइन सुधार जैसे कामों में अवैध वसूली की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि एसीबी की इस कार्रवाई के बाद विभाग में फेले भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगेगा।

जैन समाज ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन, संत सुरक्षा और रीवा घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

रीवा (मध्य प्रदेश) में विहारत आर्थिक माताजी एवं संघ के साथ हुई दुःखद घटना को लेकर अम्बिकापुर के समस्त जैन समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज ने घटना की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने तथा देशभर में विहारत साधु-संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि रीवा में हुई घटना ने पूरे समाज को गहरे दुःख और चिंता में डाल दिया है। समाज का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और वीडियो क्लिपों के आधार पर मामले की पारदर्शी जांच आवश्यक है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस प्रकरण की SIT अथवा न्यायिक जांच कराई जाए तथा घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जैन साधु-संत पूर्णतः अहिंसक, निरहंसे एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी



होते हैं, जो समाज को शांति, संयम और अहिंसा का संदेश देते हैं। ऐसे में उनके साथ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं और हमले गंभीर चिंता का विषय हैं। जैन समाज ने विहारत संतों की सुरक्षा के लिए 'संत सुरक्षा प्रोटोकॉल' लागू करने की मांग भी की। इसके अंतर्गत विहार मार्ग पर प्रशासनिक समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस सहयोग, ट्रेफिक नियंत्रण, चेतावनी संकेतक एवं हॉर्डे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को बात कही गई। इसके अलावा भारत सरकार से 'राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति' बनाने, संतों के विरुद्ध अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखने तथा स्थानीय स्तर पर 'संत सुरक्षा समन्वय प्रकोष्ठ' एवं आपात कालीन संपर्क व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई। जैन समाज ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और तपस्वी संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समाज ने प्रशासन से इस संवेदनशील विषय पर त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई। ज्ञापन सौपने के दौरान जैन समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे।

ओजस्वी सरगुजा' योजना से 55 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी NEET-JEE की निःशुल्क कोचिंग



-संवाददाता- अम्बिकापुर, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'ओजस्वी सरगुजा' योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिले के 55 मेधावी विद्यार्थियों को NEET एवं JEE परीक्षा की तैयारी के लिए रायपुर भेजा गया, जहां उन्हें प्रतिष्ठित Allen Career Institute में आवास-भोजन की सुविधा दी जाएगी। सोमवार को जिला कलेक्टर परिसर से विद्यार्थियों एवं पालकों को लेकर रवाना हुई तीन बसों को मंत्री राजेश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयोजित अभिनेदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरगुजा के उज्वल भविष्य की आधारशिला रखने वाला ऐतिहासिक क्षण है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आज चयनित विद्यार्थी भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनकर समाज का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के चयनित विद्यार्थियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन बच्चों ने साबित किया है कि प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं

होती। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, 'यह यात्रा केवल रायपुर तक की नहीं, बल्कि आपके सपनों, संघर्षों और सफलता की यात्रा है। पूरी मेहनत, अनुशासन और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ें।' कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनाशरण यादव, कलेक्टर अजीत वसंत, जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल तथा जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और पालक उपस्थित रहे।

55 विद्यार्थियों का चयन : योजना के तहत कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कुल 50 विद्यार्थियों के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के 5 अतिरिक्त विद्यार्थियों का चयन किया गया। इनमें 36 विद्यार्थी NEET तथा 19 विद्यार्थी JEE की तैयारी करेंगे।

हर महीने मिलेगी छात्रवृत्ति : विद्यार्थियों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था के लिए प्रत्येक चयनित छात्र-छात्रा को 7500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से संचालित यह योजना सरगुजा के विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी।

पीटीएस मैनपाट में 83 नवआरक्षकों का दीक्षांत समारोह संपन्न...

आईजी दीपक कुमार झा ने ली परेड की सलामी, कर्तव्यनिष्ठा का दिलाया संकल्प

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) मैनपाट में रविवार को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने परेड की सलामी ली। राज्य के विभिन्न जिलों से आए 83 नवआरक्षकों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समारोह की शुरुआत पुलिस अधीक्षक पीटीएस मैनपाट सचिंद्र चौबे के स्वागत उद्बोधन से हुई। उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले नवआरक्षकों को कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की शपथ दिलाई। आईजी दीपक कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि आरक्षक पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो सीधे आम जनता से जुड़कर कार्य करता है। उसके व्यवहार और कार्यशैली से विभाग की छवि बनती है। उन्होंने नवआरक्षकों से निष्पक्षता, मेहनत और ईमानदारी के

साथ अपने दायित्व निभाने की अपील की। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उकृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवआरक्षकों को प्रशस्तित पत्र देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत परेड का नेतृत्व परेड कमांडर दिलीप खलखो और सहायक परेड कमांडर रोहन चंद्रकार ने किया।

विभिन्न जिलों से पहुंचे नवआरक्षक : समारोह में रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 83 नवआरक्षकों ने भाग लिया।

अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट : समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे ने मुख्य अतिथि आईजी दीपक कुमार झा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता आशीष कच्छू ने किया।

स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में निकली शिक्षकों की भर्ती, 9 जून तक करें आवेदन

-संवाददाता- बलरामपुर, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

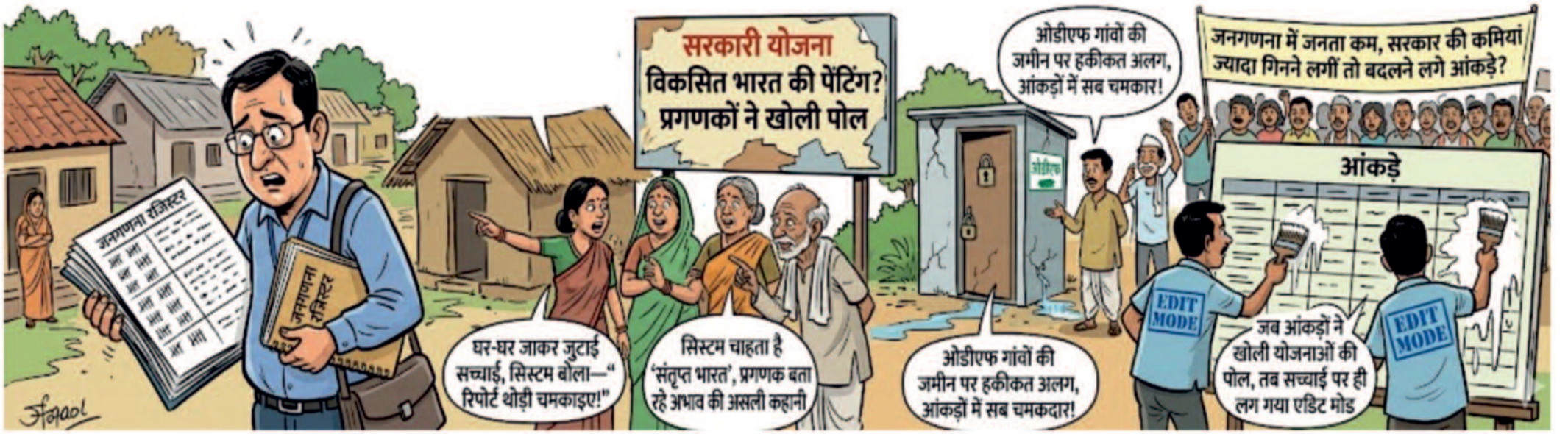
जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों की पूर्ति के लिए सविदा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव, स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई से 9 जून 2026 तक संयुक्त जिला कार्यालय स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिले के बलरामपुर, रामानुजगंज, वाडुफनगर, सेमरा-कुसमी, राजपुर, शंकरनगर,

रघुनाथनगर, रामचंद्रपुर, डौरा एवं चलगली स्थित स्वामी आत्मानंद उल्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के तहत बलरामपुर विद्यालय में सहायक शिक्षक कला (अंग्रेजी) का 1 पद, रामानुजगंज में व्याख्याता अंग्रेजी एवं सहायक शिक्षक कला समूह के 1-1 पद, वाडुफनगर में व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता वाणिज्य और व्यायाम शिक्षक के 1-1 पद रिक्त हैं। वहीं कुसमी, राजपुर, शंकरनगर, रघुनाथनगर, रामचंद्रपुर, चलगली और डौरा विद्यालयों में भी विभिन्न विषयों के शिक्षकीय पदों पर भर्ती की जाएगी।

<p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा.</p> <p>रा.प्र.क्र./अ-20(11)/2025-26</p> <p>ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रमोद निवारी व अन्य 01 आ0 / पति श्रवण निवारी जाति निवासी रिंग रोड जरागाढ़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - केदारपुर, शीट नम्बर- 1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 158 / 1, 158/4 रकबा 0.011/2, 0.011/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>आज दिनांक- 22.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>(सील) नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा.</p> <p>रा.प्र.क्र./अ-20(11)/2025-26</p> <p>ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेखा शर्मा आ0/पति व्यास नारायण शर्मा जाति, निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - केदारपुर, शीट नम्बर- 1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 158 / 1, 158/4 रकबा 0.011/2, 0.011/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>आज दिनांक- 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>(सील) नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा.</p> <p>रा.प्र.क्र./अ-20(11)/2025-26</p> <p>ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक फखरुन निशा आ0/पति जाकिर हुसैन जाति निवासी मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - परांडाई, शीट नम्बर- 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2484/40 रकबा 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>आज दिनांक- 20.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>(सील) नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर</p>	<p>न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला- सरगुजा.छ0ग0</p> <p>रा.प्र.क्र./अ-6-अ/2025-26</p> <p>ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरांत सोनी, निवासी ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 542/12, 543/90 रकबा क्रमशः 0.014, 0.006 हे. भूमि के नक्शा में हुये जुटि को सुधार किये जाने आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 12/06/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अधिष्ठाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>आज दिनांक- 22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>(सील) तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>नाम सुधार सूचना</p> <p>मैं विजय कुमार अग्रवाल पिता रमनिवास अग्रवाल उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी वार्ड नं0 38 अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0। मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार सत्य एवं सही है। कि मेरा नाम इससे पूर्व विजय अग्रवाल (VIJAY AGRAWAL) था जो अब वर्तमान में मेरा नाम विजय कुमार अग्रवाल (VIJAY KUMAR AGRAWAL) हो गया है। मेरी पति दीपिका अग्रवाल के दस्तावेजों में पति का पूर्व नाम विजय अग्रवाल (VIJAY AGRAWAL) दर्ज था जो अब वर्तमान में मेरा अर्थात् पति का नाम परिवर्तन होकर विजय कुमार अग्रवाल (VIJAY KUMAR AGRAWAL) हो गया है। जिसके समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।</p> <p>शपथग्रहिता विजय कुमार अग्रवाल</p>	<p>नाम सुधार सूचना</p> <p>मैं आकाश गुप्ता आ. श्री उपेन्द्र गुप्ता आयु 36 वर्ष, निवास का पता- चर्च रोड केदारपुर, मल्होत्रा गली अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.। यह कि, मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अभिराज कुमार गुप्ता / Abhiraj Kumar Gupta है, एवं उसकी जन्म तिथि 17/08/2014 है उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है।</p> <p>मेरे पुत्र का आधार कार्ड बना था जिसका नं0 4533 8041 2569 है जिसमें उसका नाम व जन्म तिथि सही अंकित है। मेरे पुत्र का आधार कार्ड उसके बाल्यकाल में ही बना था, जिसमें मैं अपेक्षित करवाया। अपेक्षित होने के बाद मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 4533 8041 2569 में उसका सही नाम अभिराज कुमार गुप्ता / Abhiraj Kumar Gupta तथा उसकी सही जन्म तिथि 17/08/2014 को अंकित किये जाने हेतु, स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।</p> <p>शपथग्रहिता आकाश गुप्ता</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

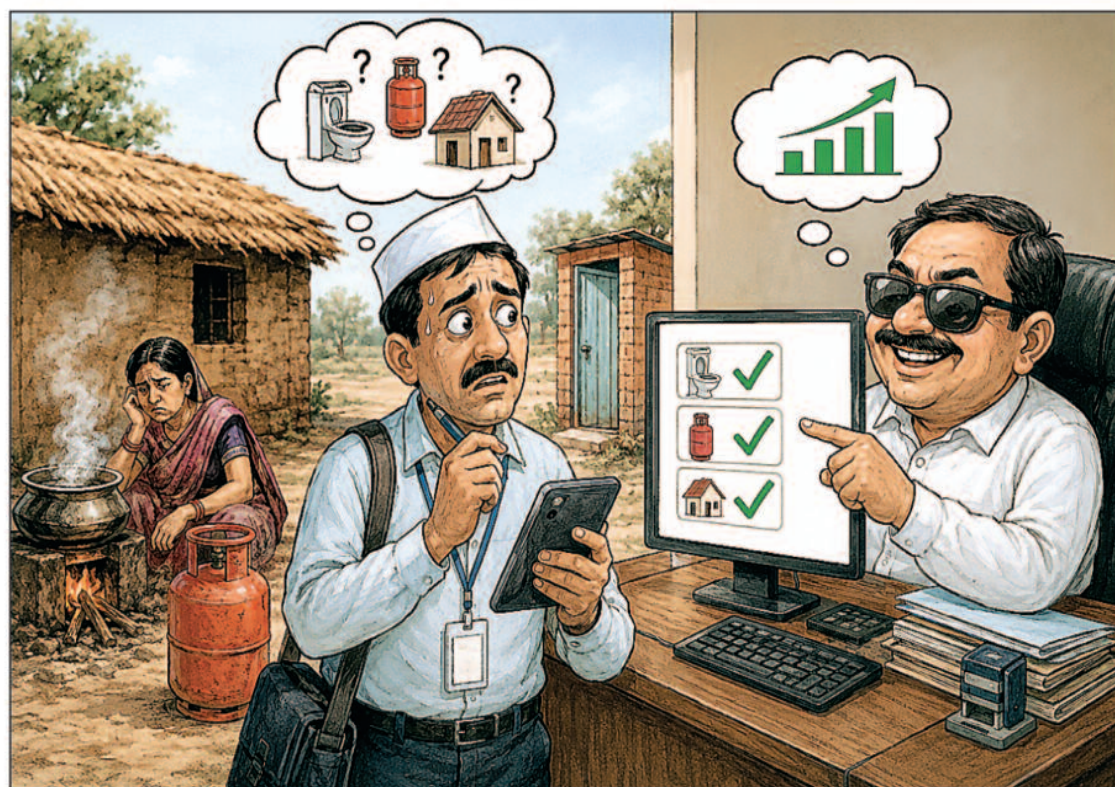
जनसंख्या गिनने निकली सरकार अपनी कमियों की गणना देखकर घबरा गई



-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया, 25 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरकार देश की जनसंख्या गिनने निकली थी, लेकिन जैसे-जैसे प्रणक गांव-गांव पहुंचे, वैसे-वैसे सरकार की योजनाओं की असली स्थिति भी गिनती में आने लगी, कहीं शौचालय सिर्फ कागज में मिला, कहीं उज्वला का सिलेंडर कोने में धूल खाता मिला, कहीं नल योजना के पाइप तो दिखे लेकिन पानी नहीं दिखा, यानी जनगणना का मकसद था लोगों की संख्या जानना, लेकिन इस दौरान सरकार की कमियों की भी जनगणना शुरू हो गई। और शायद यहीं से पूरी कहानी असहज होने लगी, प्रणकों का आरोप है कि जब वास्तविक आंकड़े सिस्टम में दर्ज होने लगे और गांवों की सच्चाई सरकारी दावों से मेल नहीं खाने लगी, तब अचानक रिपोर्ट सुधारो अभियान शुरू हो गया, अब शिक्षकों पर कथित तौर पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आंकड़े ऐसे भरे जाएं जिससे हर गांव विकसित, हर घर सुविधायुक्त और हर योजना शत-प्रतिशत सफल दिखाई दे, व्यंग्य यह है कि सरकार को शायद डर जनसंख्या बढ़ने का नहीं, बल्कि कमियों की गिनती बढ़ने का ज्यादा दिखाई देने लगा, इसलिए अब हालत यह हो गई है कि जहां लकड़ी के धुएं में रोटी बन रही है वहां एलपीजी लिखने की सलाह है, जहां लोग खुले में जा रहे हैं वहां शौचालय उपलब्ध दिखाने का दबाव है, और जहां अधूरा मकान बरसात में टपक रहा है वहां पक्का आवास दर्ज करने की बात हो रही है, यानी अब जनगणना केवल लोगों की नहीं,



बालक सरकारी छवि बचाने की कवायद बनती नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो सिस्टम कह रहा हो सच्चाई कम दिखाओ, विकास ज्यादा दिखाओ, और इसी के बाद शिक्षकों के बीच यह व्यंग्यात्मक चर्चा भी शुरू हो गई कि अगर आखिर में आंकड़े सरकार के हिसाब से ही भरने हैं, तो फिर इतनी गर्मी में घर-घर भेजने की क्या जरूरत थी? एसी कमरे में बैठकर ही पूरे जिले को संपूर्ण विकसित घोषित कर दिया जाता। बता

दे की छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से जो आवाजें निकलकर सामने आ रही हैं, वे इस पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या यह वास्तव में जनगणना है, या फिर जनभावना प्रबंधन अभियान, जिसमें गरीबी को सरकारी पोर्टल पर अपलोड होने से पहले ही संपादित कर दिया जाता है? गर्मी ऐसी कि सड़क पर अंडा फट जाए तो ऑमलेट बन जाए, उस तामपान में शिक्षक गांव-गांव घूम रहे हैं, हथ में

मोबाइल, कंधे पर बैग, माथे पर पसीना और दिमाग में प्रशिक्षण की बातें, उन्हें सिखाया गया था कि घर-घर जाकर वास्तविक जानकारी जुटानी है, किसके घर में शौचालय है, कौन लकड़ी पर खाना बना रहा है, किसके पास पानी नहीं है, कौन कच्चे मकान में रह रहा है सब दर्ज करना है, लेकिन आरोप यह है कि जब यही जानकारी ऑनलाइन दर्ज होने लगी और वास्तविक तस्वीर उभरने लगी, तब अचानक सिस्टम को विकास खतरे में दिखाई

उज्वला योजना : सिलेंडर आया, रिफिल नहीं आया

सरकार ने वर्षों तक मंचों से कहा कि गरीब महिलाओं को धूप से मुक्ति दिलाई गई, सिलेंडर बांटे गए, फोटो खिंचे, पोस्टर लग, विज्ञापन बने, लेकिन गांवों की रसोई कुछ और कहानी कह रही है, कई घरों में सिलेंडर को लोग ऐसे संभालकर रखे हुए हैं जैसे शादी में मिला कोई कीमती गिफ्ट हो, उपयोग इसलिए नहीं क्योंकि गैस भरवाना जब के बाहर है, नतीजा यह कि लकड़ी, उपले और कोयले पर ही खाना बन रहा है, अब अगर जनगणना में सबको एलपीजी उपयोगकर्ता दिखा दिया जाएगा, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि योजना का दूसरा हिस्सा अब भी अधूरा है? लेकिन शायद असली लक्ष्य समस्या हल करना नहीं, समस्या को डेटा से गायब करना है।

ओडीएफ का ऐसा जादू कि खेत भी 'शौचालय' घोषित हो जाएं!

भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के बाद लगा था कि अब गांवों की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन प्रणकों का दावा है कि कई जगह शौचालय हैं ही नहीं, और जहां हैं भी, वहां पानी नहीं, टंकी नहीं, दरवाजा नहीं या उपयोग की आदत नहीं, फिर भी अगर डेटा में सब संतुप्त दिखेंगे, तो कागज पर भारत स्वच्छ रहेगा और जमीन पर लोग अब भी खेत खोजते रहेंगे, व्यंग्य यह है कि अब शायद आने वाले समय में सरकारी रिपोर्ट यह भी कह दे कि गांवों में खुले में शौच नहीं होता, लोग प्राकृतिक वातावरण में स्वास्थ्य योग करते हैं।

कच्चे मकानों को पक्का दिखाने की कला, आंकड़ों का सीमेंट बहुत मजबूत है

प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के बड़े-बड़े दावे हुए, लेकिन जनगणना में जुटी जानकारी कथित तौर पर अलग तस्वीर दिखा रही थी, कई घर ऐसे मिले जहां दीवारें मिट्टी की, छत टिन की और बरसात में पूरा परिवार बाल्टी लेकर बैठता है, लेकिन यदि उन्हें भी पक्का मकान घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर योजना पूरी मानी जाएगी, यानी गरीब के घर में बारिश टपक रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वहां मॉडर्न हाउसिंग सुविधा उपलब्ध है।

डिजिटल इंडिया का नया अध्याय, एडिट करो और डेटा गायब करो

जनगणना में लगे शिक्षक शिक्षिका की सबसे बड़ी परेशानी तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी सामने आई है, आरोप है कि जब वे पहले से भरे डेटा को एडिट करने जाते हैं, तो पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाता है, अब जिन्होंने सारी जानकारी सीधे मोबाइल में भरी थी और कहीं नोट नहीं की, वे दोबारा गांव जाकर याददाश्त के भरोसे डेटा भर रहे हैं, इस स्थिति ने शिक्षकों को दोहरी मार दी है, पहले धूप की मार, फिर सिस्टम की मार, एक शिक्षक ने व्यंग्य में कहा कि अगर आखिर में ऑफिस में बैठकर ही आंकड़े तय करने हैं, तो हमें गांव भेजने की क्या जरूरत थी? एसी कमरे में बैठकर ही पूरे जिले को विकसित घोषित कर देते।

जनगणना या 'जन-संतुष्टि प्रमाण-पत्र वितरण योजना'?

असल सवाल यही है, अगर हर गरीब को सुविधाभोगी दिखाना है ज हर जरूरतमंद को संतुष्ट दिखाना है हेरु समस्या को उपलब्ध में बदलना है तो फिर जनगणना का उद्देश्य क्या बचता है? जनगणना इसलिए होती है ताकि सरकार को पता चले कि देश में कितने लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ताकि नीति बने, बजट बने, योजनाएं बनें, लेकिन यदि शुरुआत में ही वास्तविक तस्वीर बदल दी जाएगी, तो फिर योजनाएं किस आधार पर बनेंगी? यह वैसा ही है जैसे डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट देखकर कहे बीमारी तो है, लेकिन रिपोर्ट में स्वस्थ लिख दो, वरना अस्पताल की छवि खराब हो जाएगी।

शिक्षक बने प्रणक, प्रणक बने डेटा कलाकार

यह भी विडंबना है कि जिन शिक्षकों को बच्चों को सच और नैतिकता सिखानी चाहिए, उन्हें अब कथित तौर पर सकारात्मक डेटा निर्माण की कला सिखाई जा रही है, वे गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि असली सब अब फोड में नहीं, सिस्टम की सोच में होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वे नीति बनाते हैं, सरकार की दिशा तय करते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी।



प्रशासन की चुप्पी और जनता का सवाल

अब तक प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं, अगर प्रणकों के आरोप गलत हैं, तो स्पष्ट खंडन होना चाहिए। और अगर सही हैं, तो यह सिर्फ एक जिले का मामला नहीं, पूरे तंत्र पर सवाल है।

आंकड़ों की सजावट से हकीकत नहीं बदलती...

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई है, अगर जनगणना जैसी प्रक्रिया भी इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएगी, तो फिर गरीब सिर्फ योजनाओं में जिंदा रहेगा, जमीन पर नहीं, कागज पर गरीबी खत्म करना आसान है, लेकिन गांव की रसोई का धुआं, टूटी दीवारें, खाली पानी की टंकियां और खेत की ओर जाते लोग अब भी वही कहानी कह रहे हैं, जिसे शायद सिस्टम सुनना नहीं चाहता, और आखिर में वही सवाल सबसे भारी पड़ता है अगर सच्चाई लिखनी ही नहीं है, तो फिर इतनी गर्मी में जनगणना कराने की जरूरत क्या है?

जो दिखे वो मत लिखो, जो अच्छा लगे वो लिखो! क्या था जनगणना का प्रशिक्षण?

प्रणकों का दावा है कि प्रशिक्षण के दौरान उनसे कहा गया था कि मकान मालिक जो बताए, वही दर्ज करें, लेकिन कई शिक्षकों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए केवल कथन नहीं, भौतिक स्थिति भी देखी, और यहीं से समस्या शुरू हो गई, क्योंकि जमीन की सच्चाई सरकारी भाषणों से मेल नहीं खा रही थी, जहां गांव ओडीएफ घोषित हो चुके थे, वहां लोग आज भी खेत की मेड़ और नहर किनारे सुबह की सैर पर जाते दिखाई दिए, जहां उज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए थे, वहां रसोई में गैस सिलेंडर धूल खा रहा था और चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, लेकिन अब आरोप यह है कि शिक्षकों से कहा जा रहा है कि ऐसी जानकारी मत भरो जिससे नकारात्मक तस्वीर बने, यानी अगर घर में शौचालय नहीं है, तब भी लिखो, अगर गैस का उपयोग नहीं हो रहा, तब भी एलपीजी लिखो, अगर मकान आधा मिट्टी और आधा तिरपाल से बना है, तब भी पक्का लिखो, लगता है अब जनगणना नहीं, राष्ट्रीय सकारात्मकता अभियान चल रहा है।

■ जब जनगणना में खुलने लगी योजनाओं की पोल, तब शुरू हुआ 'रिपोर्ट सुधार अभियान'!

■ जनगणना बनी 'इमेज मैनेजमेंट योजना'? शिक्षकों के आरोपों से मचा हड़कंप

■ सरकारी योजनाओं की असलियत जनगणना में आई सामने, अब डेटा बदलने का आरोप

■ घर-घर जाकर जुटाई सच्चाई, सिस्टम बोला- रिपोर्ट थोड़ी चमकाइए!

■ कच्चे घरों को पक्का, लकड़ी के चूल्हे को गैस बताने, जनगणना में आंकड़ों का खेल?

■ जनगणना के नाम पर 'विकसित भारत' की पेंटिंग? प्रणकों ने खोली पोल

■ जनगणना या सरकारी इमेज मैनेजमेंट? कोरिया जिले से उठे बड़े सवाल

■ शौचालय बिना घर भी 'सुविधाभोगी', जनगणना में सच्चाई छिपाने का आरोप

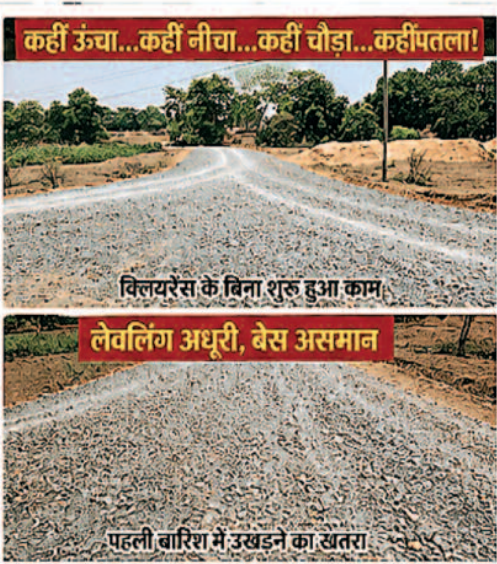
■ तपती धूप में जुटाई सच्चाई, पोर्टल पर बदलने का दबाव- जनगणना पर विवाद

■ जनगणना की गणित में गरीबी गायब! प्रणकों के आरोपों से मचा हड़कंप

■ सिस्टम चाहता है 'संतुप्त भारत', प्रणक बता रहे अभाव की असली कहानी

■ घर-घर जाओ, लेकिन सच मत लाओ!- जनगणना पर प्रणकों का बड़ा आरोप

7.40 करोड़ की सड़क में 'विकास' की धूल! नारियल फूटे तीन बार, गुणवत्ता पहली बारिश में बहने को तैयार?



- >> गंगौटी-शिवपुर सड़क में बेस कमजोर, बिल मजबूत! पीडब्ल्यूडी की इंजीनियरिंग पर उठे बड़े सवाल
- >> सड़क कम, कमीशन की लेयर ज्यादा? 7.40 करोड़ की सड़क निर्माण में तकनीकी मानकों की उड़ती धज्जियां
- >> घटिया बेस पर करोड़ों का डामर! ग्रामीण बोले जैसी बने, बस बन जाए सड़क
- >> मिट्टी बैठी नहीं, लेकिन भुगतान की तैयारी शुरू! गंगौटी-शिवपुर सड़क निर्माण पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
- >> तीन भूमिपूजन, अधूरी गुणवत्ता और भागता सिस्टम! सड़क निर्माण में विकास नहीं, जल्दबाजी ज्यादा दिखी
- >> पीडब्ल्यूडी की सड़क या बरसाती प्रयोगशाला? कहीं पतली, कहीं मोटी सड़क पर उठे तकनीकी सवाल
- >> किसानों ने जमीन दी, सिस्टम ने घटिया निर्माण दिया! 7.40 करोड़ की सड़क पर विभागीय चुप्पी
- >> वाइब्रेटर रोलर चला कम, भ्रष्ट व्यवस्था ज्यादा! गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण पर ग्रामीणों की पैनी नजर
- >> पहले फोटो, फिर फीता, अब फटाफट सड़क! खबर छपते ही हरकत में आया पूरा सिस्टम
- >> बरसात से पहले सड़क या बरसात के बाद गड्ढे? गंगौटी-शिवपुर मार्ग पर निर्माण से ज्यादा सवाल

आंकार पाण्डेय

सूरजपुर, 25 मई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर अंचल की बहुचर्चित गंगौटी-शिवपुर-नवापारा सड़क आखिरकार फिर सुर्खियों में है, वर्षों तक गड़बड़, कीचड़ और सरकारी वादों के बीच पिसे ग्रामीणों की आवाज जब लगातार खबरों के जरिए बाहर आई, तब जाकर प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और टेकेदारी सिस्टम की नौद टूटी, 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क अब तेजी से बनाई जा रही है, लेकिन निर्माण की शुरुआत ने ही गुणवत्ता पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि ग्रामीण कहने लगे हैं सड़क बन रही है या भविष्य का घोटाला? यह वही सड़क है जिसका तीन-तीन बार भूमिपूजन हुआ, हर बार नेता आए, नारियल फोड़ा गया, फीता कटा, फोटो खिंचे, सोशल मीडिया पोस्ट चमके और जनता को बताया गया कि विकास अब दौड़ेगा है, लेकिन विकास इतना धीरे दौड़ा कि सड़क बनने से पहले ही कई ग्रामीण बूढ़े हो गए, अब जब अखबारों ने सवाल उठाए, ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया और किसानों ने प्रशासन को आईना दिखाया, तब जाकर मशीनों मैदान में उतरीं, मगर सवाल यह है कि क्या यह सड़क टिकाऊ बनेगी या पहली बारिश में फिर सरकारी इंजीनियरिंग की पोल खोल देगी?

किसानों ने दिखाई इंसानियत, सिस्टम ने दिखाई बेथर्मी

इस सड़क की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन किसानों की जमीन सड़क निर्माण में गई, उन्हें आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला, फिर भी किसान अजी साहू सहित कई ग्रामीणों ने गांव और जनहित को देखते हुए अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए दे दी, यह वही किसान हैं जिन्हें चुनावी मंचों पर देश का अन्नदाता कहकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब फाइलों में उनका नाम आता है तो वही किसान सरकारी प्रक्रिया में सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क गांव के लिए जरूरी थी, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, मुआवजा फाइलों में धूमता रहा और सड़क राजनीति के मंचों पर है, विडंबना देखिए की गरीब किसान बिना मुआवजे के विकास का रास्ता दे रहा है, और करोड़ों की परियोजना में गुणवत्ता शुरू से ही संदिग्ध दिखाई दे रही है।

वया आख पर पट्टी या सुविधा की चुप्पी?

अब सबसे बड़ा सवाल पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका पर उठ रहा है, जब करोड़ों रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है, तब अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वे सब देखकर भी चुप हैं? या फिर उन्हें सिर्फ फाइलों की प्रगति दिखाई दे रही है? ग्रामीण तंत्र कस रहे हैं लगता है इंजीनियर साहब सड़क की मजबूती नहीं, बिल की मोटाई चेक कर रहे हैं, लोगों का आरोप है कि यदि शुरुआत में ही इतनी अनियमितताएं दिख रही हैं तो आगे स्थिति और खराब हो सकती है।

ग्रामीणों की मजबूरी, घटिया ही सही, पर बन जाए

इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि ग्रामीण अब गुणवत्ता की लड़ाई से ज्यादा सड़क बन जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, बरसात नजदीक है गांव की हालत हर साल खराब हो जाती है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चे स्कूल जाने में परेशान होते हैं और किसानों की उपज फंस जाती है, ऐसे में लोग कह रहे हैं जैसी भी बने, बस सड़क बन जाए, यह सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर जनता के टूट चुके भरोसे की सबसे बड़ी तस्वीर है।

तीन भूमिपूजन और राजनीति की रिटेनिंग वॉल

ग्रामीण बताते हैं कि इस सड़क का तीन बार भूमिपूजन हुआ, हर बार नेताओं ने विकास के बड़े-बड़े दावे किए। फोटो खिंचे, नारियल फूटे, भाषण हुए, लेकिन सड़क नहीं बनी, अब जब खबरों ने दबाव बनाया, तब जाकर सड़क निर्माण शुरू हुआ, लोग मजाक में कह रहे हैं इस सड़क पर डामर से ज्यादा नारियल खर्च हो चुका है।

ग्रामीणों की मांग हर लेयर की स्वतंत्र जांच हो...

अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि सड़क निर्माण की हर प्रक्रिया की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, उनकी मांग है कि मिट्टी कम्पैक्शन का एफडीटी टेस्ट सार्वजनिक हो, जीएसबी और डब्ल्यूएमएम की लैब रिपोर्ट जारी हो, सड़क की पूरी चौड़ाई डिजिटल माप से जांची जाए, निर्माण स्थल पर गुणवत्ता बोर्ड लगाया जाए, जिम्मेदार इंजीनियरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो, ग्रामीणों का कहना है कि यदि अभी निगरानी नहीं हुई तो करोड़ों रुपए की यह सड़क भविष्य में फिर सरकारी लापरवाही की मिसाल बन जाएगी।



तकनीकी मानकों की कहानी और जमीन की हकीकत

पीडब्ल्यूडी की स्वीकृति के अनुसार इस सड़क की कुल चौड़ाई 9 मीटर निर्धारित है, तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार पहले 7 मीटर हिस्से में मिट्टी भराई, पानी का छिड़काव और वाइब्रेटर रोलर से सही कम्पैक्शन होना चाहिए, इसके बाद जीएसबी (ग्रेन्युलर सब बेस) फिर डब्ल्यूएमएम (वेट मिक्स मैकेडम) और अंत में लगभग 3.90 मीटर चौड़ाई में डामर बिछाया जाना है, तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं कि सड़क निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बेस लेयर होता है, यदि मिट्टी सही तरीके से बैठी नहीं, तो ऊपर की पूरी सड़क भविष्य में धंसने और टूटने लगती है, लेकिन ग्रामीणों और मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि यहां मिट्टी डालने के बाद पर्याप्त पानी नहीं डाला गया, वाइब्रेटर रोलर औपचारिकता निभाता दिखाई दे रहा है, कई जगह बेस असमान है, कहीं सड़क ऊंची है, कहीं नीचे, कहीं चौड़ाई ज्यादा है, कहीं कम, यानी शुरुआत ही ऐसी दिखाई दे रही है कि सड़क से ज्यादा चिंता उसकी उम्र को लेकर होने लगी है।

घटिया जीएसबी और कमजोर बेस पर उठे गंभीर सवाल

सड़क निर्माण में जीएसबी यानी सड़क की रीढ़ मानी जाती है, इसमें निर्धारित गुणवत्ता के पथर और ग्रेन्युलर सामग्री का उपयोग होना चाहिए ताकि सड़क भारी वाहनों का भार सह सके, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यहां निम्न गुणवत्ता की जीएसबी सामग्री उपयोग की जा रही है, कई जगह मिट्टी मिश्रित सामग्री दिखाई दे रही है, यदि जीएसबी कमजोर होगी तो डब्ल्यूएमएम और डामर की परत भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी भराई के बाद ऑप्टिमम मांस्ट्रकर कटौत बनाए रखना जरूरी होता है, यानी मिट्टी को पर्याप्त पानी देकर रोलेर से दबाना चाहिए ताकि उसमें भविष्य में धंसाव न हो, लेकिन यहां कई जगह सूखी मिट्टी पर ही रोलेर चला दिया गया, इसका परिणाम यह हुआ कि सड़क की लेवलिंग पूरी तरह संतुलित नहीं दिख रही, भविष्य में यही सड़क दरारों और गड्ढों की फैक्ट्री बन सकती है।

कहीं पतली, कहीं मोटी - सड़क कम...प्रयोग ज्यादा...

ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क की चौड़ाई शुरू से अंत तक नापी जाए तो कई जगह भारी अंतर दिखाई देगा, कहीं सड़क मानक से कम चौड़ी है, कहीं साइड बिलियर्स नहीं हैं, तो कहीं बिना सही कटिंग किए काम आगे बढ़ा दिया गया, तकनीकी रूप से सड़क निर्माण में फॉर्मेशन विडम्ब समान होना बेहद जरूरी होता है, यदि सड़क की चौड़ाई और बेस हर जगह समान नहीं होगी तो सड़क किनारों से टूटने लगेगी, ग्रामीण व्यंग्य में कह रहे हैं लगता है सड़क इंजीनियरिंग से नहीं, अंदाजे से बनाई जा रही है।

दो-दो फीट की नाली, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर खतरा

सड़क के दोनों ओर दो-दो फीट चौड़ी नालियां बनाई जा रही हैं, लेकिन ग्रामीणों और जानकारों का कहना है कि नालियों की गहराई और ढलान तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं दिख रही, विशेषज्ञ बताते हैं कि सड़क की सबसे बड़ी दुश्मन बारिश का पानी होता है, यदि पानी सड़क के बेस में घुस गया तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी और सड़क जल्दी टूटने लगेगी, यानी यदि ड्रेनेज सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए की सड़क पहली ही बरसात में जवाब दे सकती है।

युद्ध स्तर पर काम, लेकिन गुणवत्ता आईसीयू में...

सबसे हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, मशीनों लगातार काम कर रही हैं, मजदूर तेजी से लगे हुए हैं, लेकिन गुणवत्ता जांच कहीं दिखाई नहीं दे रही, ग्रामीण पूछ रहे हैं क्या मिट्टी का Field Density Test हो रहा है? क्या GSB और WMM की लैब जांच हुई? क्या लेवल मशीन से हर हिस्से की माप ली गई? क्या इंजीनियर नियमित साइट निरीक्षण कर रहे हैं? यदि यह सब हो रहा है तो फिर सड़क का बेस शुरुआत से ही असमान क्यों दिख रहा है?

कमीशनखोरी बनाम गुणवत्ता - असली लड़ाई यही है...

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तकनीकी नहीं, मानसिकता की है, जब परियोजना की शुरुआत गुणवत्ता से नहीं बल्कि कितना ऊपर जाएगा से होती है, तब सड़क की उम्र पहले दिन ही तय हो जाती है, लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण अब विकास नहीं, बल्कि कमीशन आधारित इंजीनियरिंग बन चुका है। जहां सड़क की मोटाई से ज्यादा प्रतिशत की परतें मजबूत होती हैं।

सबसे बड़ा सवाल, क्या पहली बारिश में खुल जाएगी पोल?

तकनीकी विशेषज्ञ साफ मानते हैं कि यदि अभी गुणवत्ता सुधार नहीं हुआ तो पहली तेज बारिश के बाद सड़क की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी, कमजोर बेस, खराब कम्पैक्शन, घटिया जीएसबी और असमान लेवलिंग भविष्य में धंसाव और गड्ढों का कारण बन सकती है, फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जांच समिति बनेगी नोटिस जारी होंगे टेकेदार सफाई देगा और जनता फिर गड्ढों में सफर करेगी।

सड़क बन रही है या भरोसा टूट रहा है?

गंगौटी-शिवपुर सड़क अब सिर्फ सड़क परियोजना नहीं रही, यह सरकारी जवाबदेही, तकनीकी ईमानदारी और ग्रामीण धैर्य की परीक्षा बन चुकी है, एक तरफ किसान बिना मुआवजे के विकास का रास्ता खोल रहे हैं, दूसरी तरफ विभागीय उदसीनता और टेकेदारी मॉडल उस रास्ते को शुरुआत से ही कमजोर बनाने में जुटा दिखाई दे रहा है, खबरों के दबाव में काम तो शुरू हो गया, लेकिन अब जनता सिर्फ सड़क नहीं देख रही...जनता मिट्टी की हर परत, रोलर की हर आवाज और डामर की हर मोटाई पर नजर रख रही है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सड़क का नहीं...7 करोड़ 40 लाख रुपए के भरोसे का है।

इधर रणवीर सिंह पर लगा बैन, उधर हाथ लगी शाह रुख खान की 350 करोड़ की बजट वाली बड़ी फिल्म?

सुपरस्टार रणवीर सिंह का नाम इस वक्त उनकी एक अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फिल्म धुरंधर 2 की अपार सफलता के बाद बतौर अभिनेता रणवीर सिंह का कद काफी ऊंचा उठा है। सही मायनों में निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर फ्रेंचाइज ने उनको इंडस्ट्री का नया सुपरस्टार बना दिया है। अब खबर आ रही है कि रणवीर के हाथ सुपरस्टार शाह रुख खान की एक बड़ी फिल्म लग गई है, जिसका बजट 350 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। ये खबर उस वक्त सामने आई है, जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज उन पर बैन लगाने का एलान किया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में जानते हैं।

रणवीर सिंह के हाथ लगी ये फिल्म

थोड़ी देर पहले निर्माता फरहान अख्तर की बहुचर्चित फिल्म डॉन 3 के विवाद को मद्देनजर रखते हुए एफडब्ल्यूआईसीई ने एक्शन लेते हुए सभी निर्माताओं से अपील की है कि वह रणवीर सिंह को अपनी फिल्म में कास्ट न करें और एक तरह से एक्टर पर प्रतिबंध लगाया है। इन सब के बीच ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि धुरंधर स्टार की एंटी शाह रुख खान की फिल्म किंग में हो गई है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली शाह रुख खान की किंग का बजट मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 350 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह इस बिग बजट वाली मूवी एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जोकि कैमियो रोल के तौर पर रहेगा। उनका कैरेक्टर किंग



फिल्म की कहानी के हिसाब से काफी जरूरी साबित होगा। हालांकि, किंग में रणवीर सिंह की एंटी को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो रणवीर पहली बार किंग खान के साथ बड़े पर्दे पर काम करते हुए नजर आएंगे

किंग की कास्ट



सुपरस्टार शाह रुख खान की किंग एक मल्टी स्टार फिल्म है, जिसमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, राघव जुवाल, अनिल कपूर, सोनम शुकला, दीपिका पादुकोण और अब रणवीर सिंह जैसे कलाकार अहम किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि किंग को इस साल क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

दो दशक बाद फिर लौटा वीवा का जादू

नेहा भसीन ने याद किए पुराने सुनहरे दिन

एक समय था जब दोस्तों को मोबाइल फोन में ब्लूथूथ से गाने भेजा करते थे और फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे। उसी दौर में भारत के पहले पॉप गल बँड वीवा ने संगीत की दुनिया में ऐसा जादू चलाया था, जिसने पूरे एक दौरे को अपनी धुनों से जोड़ दिया। उनके गाने 2000 के दशक के युवाओं की यादों का हिस्सा बन गए थे। अब करीब दो दशक बाद वीवा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, बँड का संगीत अब डिजिटल और ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दोबारा उपलब्ध कराया जा रहा है। वीवा की शुरुआत पांच मेंबर के जरिए बँड के रूप में हुई थी। इस बँड में सीमा रामचंदानी, नेहा भसीन, प्रतीची महापात्रा, महुआ कामत और अनुष्का मनचंदा शामिल थीं। उस समय भारतीय पॉप संगीत में गल बँड का कॉन्सेप्ट नया था और वीवा ने अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि, पहले एल्बम के बाद सीमा रामचंदानी ने बँड छोड़ दिया था। इसके बाद बाकी चार सदस्यों ने मिलकर 2003 में वीवा! रिलीज नाम से अपना दूसरा एल्बम रिलीज किया था। अब वीवा ने जियोस्टार के साथ मिलकर अपने

संगीत को फिर से लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया है। बँड के गाने और वीडियो अब कानफोड और दूसरे बड़े ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इस खबर ने उन लोगों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया है, जो 2000 के दशक में वीवा के गानों को सुनते हुए बड़े हुए थे। इस खास मौके पर नेहा भसीन ने कहा, वीवा सिर्फ एक बँड नहीं था, बल्कि यह एक एहसास और एक पूरे दौर की पहचान बन गया था। मेरे लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने उस समय उनके गाने सुने, वीवा एक खूबसूरत याद की तरह है। भारत के पहले पॉप गल बँड के रूप में उन्होंने कुछ बहुत खास



बनाया था और यह रिश्ता आज भी लोगों के प्यार की वजह से जुड़ा है। नेहा भसीन ने कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब नई पीढ़ी भी उन गानों और वीडियो को सुन और देख सकेगी, जिन्होंने एक समय लाखों युवाओं की यादों को खास बनाया था। संगीत का सपना सुंदर रहलू यही होता है कि वह समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में बना रहता है।

260 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली थी धर्मेन्द्र की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

धर्मेन्द्र की एक फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी कि आज भी कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। यह फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई है। 60 दशक का दौर था, सिनेमा में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे सितारों का राज था और इसी बीच पंजाब से एक गबरू जवान अभिनेता बनने आ गया। पर्सनेलिटी ऐसी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि दिलीप कुमार भी उनके कायल हो गए थे और कह दिया था-अल्लह, मेरे को ऐसे ही बनाया होता तो क्या हो जाता। इस आर्टिकल में हम जिस गबरू जवान की बात कर रहे हैं, वो है सिनेमा के ही-मैन धर्मेन्द्र। उन्होंने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मगर उन्हें पहचान फूल और पत्थर से मिली। मगर यह उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है।



बड़े पर्दे पर छाई रही। कमाई दोगुना-तिगुना हुई।

धर्मेन्द्र के फिल्म ने बनाया था रिकॉर्ड

यह फिल्म है रमेश सिप्पी निर्देशित शोले। सिनेमा के इतिहास की सबसे कल्ट फिल्मों में शुमार शोले में धर्मेन्द्र ने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन, अमजद खान जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। 1975 में आई यह फिल्म पचास साल बाद भी कल्ट बनी हुई है। शोले ने कई

बड़े रिकॉर्ड बनाए जिसमें से एक यह था कि यह सबसे कमाई वाली फिल्म थी। हालांकि, इस फिल्म का अभी भी एक रिकॉर्ड ऐसा है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। यह फिल्म पूरे भारत में 60 गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड बना चुकी है। यह ऐसी फिल्म है जिसने 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई। यही नहं, मुंबई के मिर्जा थिएटर में शोले पांच सालों तक चलती रही थी।

पांच गुना ज्यादा की थी कमाई

बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इसने दुनियाभर में कमाई से इतिहास रच दिया था। करीब 3 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में पांच गुना मुनाफा कमाया था। फिल्म का कारोबार 15 करोड़ से ज्यादा था।



टीजर और टाइटल ट्रेक के बाद, वेलकम टू द जंगल के मेकअप ने अब फिल्म का एक नया ट्रेक रिलीज किया है जिसका टाइटल है घिस घिस घिस। यह भोजपुरी गाना है जिसे विक्रम मोंट्रोस ने कंपोज किया है, और मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक ने गाया है। यह एक प्रॉपर भोजपुरी ट्रेक है जिसमें कुछ किंग, एडल्ट लिखिस है। वीडियो में

है, और गणेश आचार्य ने परफेक्ट कोरियोग्राफी की है। घिस घिस गाने पर नेटिजन्स का रिएक्शन खैर, गाने ने यकीनन सबका ध्यान खींचा है, और नेटिजन्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक नेटिजन्स ने ट्वीट किया, बवाल गाना है, डांस और एक्सप्रेशन थकपन से भरा हुआ है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, भोजपुरी टच इस और भी

अक्षय कुमार का नया डांस नंबर चर्चा में, नेटिजन्स ने बताया एनर्जेटिक

मजेदार बना रहा है। एक और नेटिजन्स ने ट्वीट किया, थिएटर पर फायर मोड फटेगा यूपी बिहार दिल्ली वालों से। अक्षय कुमार के अलावा, वेलकम टू द जंगल में सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, दलेर मेहदी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, उर्वशी रौतेला, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, कीकू शारदा, फिरोज खान (अर्जुन), सुदेश बेरी और वृही कोडवारा हैं।

माता-पिता से छुपकर बॉबी देओल ने दिया इंटीमेट सीन, भाई सनी से भी रखा राज

हाल ही में, अभिनेता बॉबी देओल ने खुलासा किया कि उन्होंने आश्रम में इंटीमेट सीन्स के बारे में पहले परिवार को नहीं बताया था। बॉबी देओल का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। एक दौर ऐसा आया, जब उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था। तब उनके पास ऑटोटी वेब सीरीज आश्रम आई जिसमें अभिनेता ने इंटीमेट सीन्स से हर किसी को हैरान कर दिया था। हाल ही में बॉबी देओल ने एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम में इंटीमेट सीन शूट करने के पीछे की कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि वह सीन करने से झिझक रहे थे। हालांकि, उन्होंने यह किया और अपने परिवार के सामने यह राज भी रखा।

परिवार से छुपाई इंटीमेट सीन की बात

रोजर सुमन के चैट शो में बात करते हुए बॉबी देओल ने बताया कि शुरू में उन्होंने आश्रम और अपने किरदार से जुड़े डिटेल्स परिवार से छुपाए थे। उनके परिवार को नहीं पता था कि वह सीरीज में इंटीमेट सीन शूट करेंगे।



खेल समाचार

लिवरपूल के निराशाजनक पांचवें स्थान पर रहने के बाद अर्ने स्लॉट ने अपनी गलतियां मानी

लंदन, 25 मई 2026। लिवरपूल के मैनेजर अर्ने स्लॉट ने अपनी टीम के निराशाजनक प्रीमियर लीग अभियान का ईमानदारी से आकलन किया। उन्होंने माना कि इस सीजन के दौरान उन्होंने हमेशा सही फैसले नहीं लिए। इस सीजन को उन्होंने सिर्फ एक शब्द में बयां किया चोट। लिवरपूल का खिताब बचाने का सफ़र निराशा के साथ खत्म हुआ। सीजन के अपने आखिरी मैच में चेंटफोर्ड के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद वे लीग में पाँचवें स्थान पर रहे। चोटों, ड्रेसिंग-रूम में तनाव और लगातार अच्छे प्रदर्शन की कमी वाले इस उथल-पुथल भरे अभियान के बाद वे बेहतर स्थिति में फोनिश करने से चूक गए। इस सीजन पर बात करते हुए, स्लॉट ने अपनी कमियों को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि हर फ़ैसला टीम के सबसे अच्छे हित को ध्यान में रखकर ही लिया गया था। स्लॉट ने कहा, यह वैसा नहीं है जैसा मैं इस सीजन की शुरुआत से पहले हासिल करना चाहता था। लेकिन, इस सीजन में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं खुश हूँ कि हमने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है।



फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले मेस्सी की फिटनेस को लेकर बड़ी चर्चा

मियामी, 25 मई 2026। अर्जेंटीना के लेजेंड लियोनेल मेस्सी के चोटिल होने की चिंता तब बढ़ गई जब सोमवार को नु स्टैडियम में (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से) मेजर लीग संकर मैच में फ्लॉरिडालिया यूनिवर्सिटी पर इंटर मियामी की 6-4 की जीत के 73वें मिनट में वह मैदान छोड़कर चले गए। न्हें अपनी बाई जांच पकड़कर सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर जाते देखा गया। यह फीफा वर्ल्ड कप से पहले हुआ है, जिससे 11 जून से 19 जुलाई तक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेंगे। अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा।



रोहित शर्मा-हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री अवॉर्ड

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पद्म श्री अवॉर्ड दिया...

नई दिल्ली, 25 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 2026 के पहले पद्म अवॉर्ड्स दिए। दरअसल, सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। इस क्रम में पहले फेज में देश की 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया। जबकि, शेष विजेताओं को दूसरे चरण में अवॉर्ड दिए जाएंगे।

राष्ट्रपति मुर्मु ने सोमवार के पहले फेज में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। जिन हस्तियों



को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, उनमें अभिनेता आर माधवन, क्रिकेटर

रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया के अलावा पैरा एथलीट प्रवीण कुमार शामिल हैं। खास बात यह है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएँ भी शामिल हैं। इसके साथ ही 16 ऐसी हस्तियाँ हैं, जिन्हें मरणोपरान्त पुरस्कार दिए गए हैं।

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब टीम इंडिया के लिए केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। बात करें रोहित शर्मा के करियर की तो अपने करियर में उन्होंने 67 टेस्ट, 282 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले

खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 12 शतक और 18 अर्धशतक के चलते 4301 रन बनाए हैं। वनडे में हिटमैन ने 33 सेंचुरी और 61 अर्धशतक के चलते 11577 रन बनाए हैं। वहीं टी20 में रोहित शर्मा ने 5 शतक और 32 अर्धशतक के बूते 4231 रन बनाए हैं।

हरमनप्रीत कौर का इंटरनेशनल करियर

हरमनप्रीत कौर ने अपने करियर में अब तक भारत के लिए 7 टेस्ट, 164 वनडे और 195 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 230, वनडे में 4541 तो टी20 में 3991 रन बनाए हैं। टेस्ट में हरमनप्रीत के नाम 1 फिफ्टी है। वनडे में 7 शतक और 24 अर्धशतक हैं जबकि टी20 में 1 शतक और 16 अर्धशतक हैं।



पहले क्वालिफायर में दमदार रहा है आरसीबी का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 25 मई 2026। आईपीएल 2026 का पहले क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मंगलवार (26 मई) को खेला जाना है। इस मुकाबले की मेजबानी धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम करेगा। आरसीबी का रिकॉर्ड पहला क्वालिफायर खेलते हुए शानदार रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने इससे पहले तीन बार पहले क्वालिफायर का टिकट हासिल किया है। साल 2011 में आरसीबी पहले क्वालिफायर में पहुंची थी, लेकिन उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2016 में टीम ने टॉप 2 में रहते हुए पहले क्वालिफायर का टिकट कटायो था। आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले क्वालिफायर में गुजरात लायंस को मात दी थी। तीसरी बार आरसीबी ने पहला क्वालिफायर पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में खेला था और रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम ने पंजाब किंग्स को शिकस्त देते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। आरसीबी 3 बार पहले क्वालिफायर में पहुंची है, जिसमें से टीम ने 2 बार जीत का स्वाद चखा है, तो एक दफा हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी ने आईपीएल में अब तक चार बार फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन टीम सिर्फ एक बार ही खिताब को अपने नाम कर सकी है। पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 18 साल का सुधा खत्म करते हुए पहली बार आईपीएल की टॉपी पर कब्जा जमाया था। आईपीएल 2026 में भी टीम ने अब तक शानदार क्रिकेट खेला है। आरसीबी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इस सीजन काफी संतुलित दिखाई दी है। टॉप ऑर्डर में विराट कोहली और देवदत्त पंडित का प्रदर्शन दमदार रहा है। खासतौर पर विराट कप्तान की लय में दिखाई दिए हैं और वह इस सीजन 557 रन बना चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने भी प्लेइंग इलेवन में आने के साथ ही बल्ले से छाप छोड़ी है।

छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपती पद्मश्री से सम्मानित

सीएम साय ने दी बधाई,कहा...सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता राष्ट्र निर्माण का श्रेष्ठ उदाहरण

रायपुर, 25 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा और अंबुझमाड़ जैसे दूर-दराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर दंपती डॉ. रामचंद्र त्रयम्बक गोडबोले और डॉ. सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान मिला है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह फेज 1 में गोडबोले दंपती को यह सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर दंपती लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में लोगों का इलाज कर मानव सेवा का काम कर रहे हैं। उनके इस समर्पण और सेवा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और डॉक्टर सुनीता गोडबोले ने अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का फ्री में इलाज किया है। समाज सेवा के लिए दंपती को अवार्ड मिला है। साल 2026 में देशभर की कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। पहले चरण में 66 लोगों को सम्मानित किया गया है, जबकि बाकी 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मान मिलेगा। हालांकि, दूसरे चरण की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है।



बस्तर के 'डॉक्टर भैया' और 'भामी' को श्री पद्मश्री सम्मान

डॉ. रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले दत्तेवाड़ा के आदिवासी इलाके में पिछले 35 साल से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ये दोनों पति-पत्नी हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले हैं। 1990 में बरसूर (दत्तेवाड़ा) आकर बस गए। तब से ये दक्षिण बस्तर, बीजापुर और सुकमा के वनवासी समुदाय की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गोडबोले दंपती रूर योजना के तहत बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दूर-दराज के गांवों में मेडिकल कैम्प लगाते हैं। लगातार फॉलो-अप करते हैं।

मेरे सभने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान : डॉ. रामचंद्र

डॉ. रामचंद्र जिन्हें लोग प्यार से 'डॉक्टर भैया' कहते हैं, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। वहीं सुनीता गोडबोले आदिवासी महिलाओं के संगठन और स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार भी देते हैं। डॉ. गोडबोले का कहना है कि मेरे सामने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान है।



मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के सुदूर जनजातीय अंचलों में दशकों से निःस्वार्थ चिकित्सा सेवा और मानवता की मिसाल प्रस्तुत करने वाले डॉ. रामचंद्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। इन दोनों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाना जनसेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के मूल्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोडबोले दंपती को यह सम्मान प्रदान किया जाना जनसेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के मूल्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोडबोले दंपती ने वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़कर अपना संगणन जीवन जनजातीय समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बस्तर के बरसूर जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम वनांचल में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों तक निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता और जनविद्यवासा का प्रकाश पहुंचाया। कुपोषण मुक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण-जनजातीय समाज में स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करने में उनका योगदान अत्यंत अनुकरणीय और प्रेरणादायी रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के सबसे दूरस्थ और जरूरतमंद लोगों के बीच कार्य किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर डॉ. रामचंद्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सेवा भावना समाज में करुणा, दायित्व और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को और मजबूत करेगी।

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अंतिम सूची जारी

रायपुर, 25 मई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन मई 2026 के लिए नाम वापसी और संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अर्धस्थायी अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस बार चुनावी रण में नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह निर्वाचन जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खाली पड़े और नए जनप्रतिनिधियों के चुने जाने से स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग बुथों पर मतदाताओं की सुविधा के पूरुषा इंतजाम स्थानीय नगरिकों को बड़ी राहत देगा।



पुनाव मैदान की पूरी तस्वीर

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत पंच पद के कुल 1136 पद तय थे, जिनमें से 640 पदों पर निर्वाच्य निर्वाचन संयोजन हो चुका है, जबकि 385 पदों पर कोई नामांकन नहीं मिला और 4 निरस्त हुए; अब शेष 107 पदों पर मतदान होगा जिसके लिए 246 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच के 82 पदों में से 15 पर निर्वाच्य चुनाव हुआ, 30 पर नामांकन नहीं आए, तथा 34 पदों पर मतदान के लिए 105 अर्धस्थायी आमने-सामने हैं। जनपद सदस्य के सभी 10 पदों पर सर्विरोध चुनाव होगा, जहां 41 प्रत्याशी

मैदान में हैं। दूसरी ओर, नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के कुल 71 स्थानों पर चुनाव होगा है, जिसके लिए 221 उम्मीदवार मैदान में होंगे हैं। वहीं, अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए 19 अर्धस्थायी के बीच मुकाबला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम और पंचायतों के चुनाव मतपेट्टी (बैलेट बॉक्स) के माध्यम से कराए जाएंगे। मतदान मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच 29 मई 2026 से शुरू की जा रही है। पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों को मिलाकर कुल 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंच पद के लिए निर्धारित 1136 पदों में से रिकार्ड 640 पदों पर निर्वाच्य निर्वाचन संयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग अजय सिंह के निदेशानुसार, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं। मई और जून के तपते मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए छाया, ठंडे पेयजल और मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि मतदान प्रतिशत पर गर्मी का असर न पड़े।

इबोला को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट... रायपुर एयरपोर्ट में बढ़ाई गई निगरानी यात्रियों की होगी सख्त जांच



रायपुर, 25 मई 2026। दुनियाभर में इबोला वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच अब अनिवार्य रूप से की जाएगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा की ओर से जारी निर्देशों के बाद एयरपोर्ट परिसर में संक्रमण रोकथाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर को एयरपोर्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्क्रीनिंग और निगरानी व्यवस्था का समन्वय प्रभावी ढंग से किया जा सके। निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जाएगी और किसी भी संदिग्ध मरीज की पहचान होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही आइसोलेशन, रेफरल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को भी पूरी तरह तैयार रखने कहा गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि संभावित संक्रमण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

बीएलओ ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, दो कर्मचारी निलंबित

खैरागढ़, 25 मई 2026। खैरागढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीएलओ कार्यालय से जुड़े कथित शराब पार्टी और वायरल वीडियो मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो और लगातार उठ रहे सवाल को बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जारी आदेश के मुताबिक, बीएलओ कार्यालय खैरागढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 विनय सिंह गहबरवार और शासकीय प्राथमिक शाला सडी के प्रधान पाठक सुनील कुमार वर्मा को निलंबित किया गया है। दोनों पर शासकीय कार्यालय परिसर में शराब सेवन और अन्यायित व्यवहार का आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जानकारी मिली थी। प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

बीजापुर में 10 करोड़ का तैदुपता जलकर राख..वन विभाग ने किराए के गोदाम में रखवाए थे 18 हजार बोरे

बीजापुर, 25 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार दोपहर निजी तैदुपता गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां रखे लगभग 18 हजार बोरे जलकर खाक हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि हलात को देखते हुए वन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। वन विभाग ने तैदुपता स्टोरेज के लिए गोदाम को किराए पर लिया था। जहां 10 दिनों में तैदुपता के 18 हजार बोरे स्टोर किए गए थे। फ्लिहाल, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग बुझाने कोतवाली थाना क्षेत्र के इंटपाल इलाके की है। जानकारी के अनुसार, इंटपाल इलाके में वन विभाग ने तैदुपता स्टोरेज के लिए एक किराए का गोदाम लिया था, जिसमें दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। उस समय गोदाम में तैदुपता के 18 हजार से ज्यादा बोरे रखे थे।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 109 के पार..रायपुर में 107.96 लीटर

रायपुर, 25 मई 2026। देशभर में तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। 25 मई को पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल का प्राइस 109 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.96 हो गई है। इससे पहले 15 मई को 3-3 रुपए, 19 मई को 90-90 पैसे और 23 मई को भी 90 पैसे प्रति लीटर रेट बढ़ाए गए थे। इस महीने ये चौथी बार दाम बढ़ा है। ब्लैक मार्केटिंग पर नजर, शिकायत के लिए नंबर जारी पशू संकट और बढ़ती कीमतों के बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल-डीजल की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शहर में कहीं भी अधिक कीमत वसूली या अवैध बिजली की जानकारी मिलने पर लोग 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ताजा रेट के मुताबिक, बस्तर और सरगुजा संभाग के

इस महीने चौथी बार छत्तीसगढ़ में पेट्रोल ₹109 के पार रायपुर में ₹107.96 प्रति लीटर डीजल भी महंगा

राजधानी	अंधा	अंधा
पेट्रोल	₹109.65	₹107.96
डीजल	₹109.59	₹109.09

जिलों में ज्यादा कीमत बढ़ी है। वहीं, रायपुर और कोरबा जैसे शहरों में बाकी जिलों की तुलना में थोड़ी राहत है। नारायणपुर में पेट्रोल 109.65 प्रति लीटर, जगदलपुर में 109.64, दत्तेवाड़ा में 109.60 और बीजापुर में 109.59 लीटर बिक रहा है। जशपुर में पेट्रोल 109.52, सरगुजा में 109.39 और अंबिकापुर में 109.09 प्रति लीटर, रायगढ़ में 109.3 रुपए दर्ज किया गया। बता दें कि इस महीने चौथी बार

टीएस सिंहदेव ने पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि पर केंद्र को घेरा...पुनाव बाद सरकार ने जनता को लूटना शुरू किया, विदेश नीति पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता को लूटना शुरू कर दिया है और महंगाई पर नियंत्रण के लिए उसके पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। मीडिया से बातचीत में सिंहदेव ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन चुनाव खत्म होते ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे महंगाई बढ़ाकर लोगों पर बोझ डाल रही है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार लगातार कहती रही कि देश में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। सिंहदेव ने केंद्र की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर दो तेल उत्पादक देशों से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया। इससे अन्य देशों से संबंध खराब हुए और अब जब डीजल-पेट्रोल की कमी हो रही है, तो कीमते बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है।

पेट्रोल 107.63 प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा जांजगीर में 108.21 और कवर्धा व रायगढ़ में 108.86 प्रति लीटर रेट सामने आया है। जानकारों के मुताबिक, बस्तर और सरगुजा संभाग में ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट ज्यादा होने के कारण पेट्रोल की कीमतें ज्यादा रहती हैं। वहीं बड़े शहरों और औद्योगिक जिलों में सप्लाई बेहतर होने से

2 साल से जेल में बंद निरंजन दस को सुप्रीम कोर्ट से राहत सुप्रीम कोर्ट ने आईएस निरंजन दस को जमानत दी

रायपुर, 25 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दस को कई करोड़ रुपये के शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और मुकदमों के निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मुख्य मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों और संबंधित मनी लाँड्रिंग मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व आयुक्त को यह राहत प्रदान की। इससे पहले अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी को भी जमानत मिल चुकी है। पीठ ने कहा कि दस को कथित तौर पर इस मामले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है, और उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में भूमिका निभाई ताकि अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाया जा सके। जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दस को दो अलग-अलग मामलों में क्रमशः 18



सितंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन पर वही जमानत शर्तें लागू की जो अन्य सह-आरोपियों पर लागू हैं। इसके तहत उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वह केवल मुकदमों की सुनवाई तथा जांच में शामिल होने के लिए ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वह भविष्य में जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले एक माच को हाइकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सोएमओ) में उप सचिव रहें सोम्या

चौरसिया को भी शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी थी। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर लंबी बहस हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों और मनी लाँड्रिंग केस में निरंजन दस को राहत दी है। दस को सितंबर और दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने निरंजन दस को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया था। आरोप था कि उन्होंने सरकारी नीति को ऐसा घुमाया जिससे उनके साथियों को फायदा पहुंचे। हालांकि, कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दे दी है। पर पाबंदी ऐसी है कि वे राज्य की सीमा में कदम नहीं रख पाएंगे। इससे पहले अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी और सोम्या चौरसिया को भी कोर्ट से राहत मिल चुकी है। रायपुर के आबकारी दफ्तरो और राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के बाद से ही हलचल तेज हो गई है।

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट



रायपुर, 25 मई 2026। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुरासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

गर्भपात के बाद दोबारा प्रेगनेंसी पर भी मिलेगा पूरा अवकाश : हाईकोर्ट

बिलासपुर, 25 मई 2026। कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है, और वह उसके बाद दोबारा गर्भवती होती है, तो पिछला अवकाश उसके नए मातृत्व अवकाश के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। महिला अपने दूसरे गर्भधारण के लिए कानूनन पूरी मातृत्व छुट्टी पाने की हकदार है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को रद्द कर दिया है। मामले में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बता दें, कि भारतीय खाद्य निगम रायपुर में अतिरिक्त ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ महिला कर्मचारी वर्ष 2019 में



गर्भवती हुई थीं। उनके जुड़वा बच्चे होने थे, लेकिन गर्भी चिकित्सीय जटिलताओं के चलते 25 अप्रैल 2019 को अस्पताल में उनका एक भ्रूण मिसकैरेज हो गया। डॉक्टरों की निगरानी और बेड रेस्ट के बाद उन्होंने 3 सितंबर 2019 को एक प्री-मैथ्योर बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश और नियमों के अनुसार

कि याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश और गर्भपात के नियमों के तहत कुल 90 दिनों की छुट्टी की हकदार हैं, जिसे विभाग कम नहीं कर सकता। कोर्ट ने लीव बैलेंस न होने के नाम पर महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को निरस्त कर दिया और रकम वापस करने के आदेश दिए। इसके अलावा महिला कर्मचारी के बाकी बचे 3 लाख 76 हजार 773 रुपए के मेडिकल बिलों के भुगतान पर निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों की दोबारा से जांच कर तय उचित आदेश जारी करें। हाईकोर्ट ने मैट्रिनिटी बेंचिफिट एक्ट, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश का अधिकार एक महिला का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, यह उसके सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है।